04 - एसआईआर अपडेट से बदल सकता है यूपी का चुनावी नक्शा

05 - यथार्थ की जमीन तलाशते मानव अधिकार

A Daily News Magazine
भोपाल
शनिवार, 20 दिसंबर, 2025

06 - भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष पवन पाटीदार का पहली बार...

07 - अंतर्राष्ट्रीय मानक पूर्ण कर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायसेन बना...

भोपाल एवं इंदौर से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 23, अंक 110, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

सुबह सवेरे

subahsaverenews@gmail.com
facebook.com/subahsaverenews
www.subahsavere.news
twitter.com/subahsaverenews

शरद की सुबह

रात .....
पंजों के बल खड़े हो कर
झांकती रहती है
नींद के रंगमहल में
सपनों का
प्रवेश निषेध है
आसमान का
एक एक सितारा गिन लेती हैं
मुंदी हुई आँखें ।
बिस्तर पर
चींटियों की तरह काटते हैं
जज़्बात
अँधेरे में .....
फर्श पर बिखरे
राई के दानों सा बीना जाता है
एक एक अक्षर
तब जा कर कहीं
बड़ी नजाकत से
उतरती है
सुबह के काग़ज़ पर
एक अदद कविता ....!!

– संध्या सिंह

प्रसंगवश

उत्तर प्रदेश में एसआईआर को लेकर बीजेपी क्यों है चिंतित ?

प्रशांत श्रीवास्तव

उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) एक अप्रत्याशित मुद्दे को लेकर चिंतित है–चुनावी सूची का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR)। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इसे अब तक एक सामान्य प्रक्रिया बताता रहा है। सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात पर चिंता जताई है कि संशोधित मतदाता सूची में बीजेपी समर्थकों का एक बड़ा हिस्सा बाहर हो सकता है। एक और चिंता यह है कि शहरी इलाकों, जिनमें एनसीआर भी शामिल है, उसमें पार्टी की पकड़ कमज़ोर हो सकती है। यहां कई लोग दूसरे राज्यों से हैं और वे अपने गृह नगर की मतदाता सूची में ही अपना नाम बनाए रखना चाहते हैं।

तीसरी बात, सूत्रों के मुताबिक, बूथ-स्तरीय एजेंट (बीएलए) नियुक्त करने की प्रक्रिया जो यह सुनिश्चित करने के लिए होती है कि प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी रहे–विपक्ष को ज़मीनी स्तर पर बेहतर तरीके से संगठित होने में मदद कर रही है। कई सालों से बीजेपी की चुनावी मशीनरी को राज्यों में संगठन के मामले में सबसे मजबूत माना जाता रहा है।

SIR की शुरुआत इस साल की शुरुआत में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले हुई थी।

देश के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में SIR की शुरुआत 4 नवंबर को हुई थी और इसे एक महीने में पूरा किया जाना था, लेकिन पिछले हफ्ते चुनाव आयोग ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा के अनुरोध पर इसकी समय-सीमा बढ़ाकर 26 दिसंबर कर दी। एक सूत्र ने बताया कि रविवार को यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा के लिए हुए एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने पार्टी पदाधिकारियों को चेतावनी दी कि करीब चार करोड़ मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हट सकते हैं और इनमें से '85 से 90 प्रतिशत' 'हमारे' हैं। कार्यक्रम में आदित्यनाथ ने कहा, 'यूपी की आबादी करीब 25 करोड़ है। इसमें से लगभग 65 प्रतिशत मतदाता होने चाहिए, जिनमें 18 साल के होने वाले लोग भी शामिल हैं। इस हिसाब से मतदाताओं की संख्या 16 करोड़ होनी चाहिए, लेकिन अब तक SIR की गिनती 12 करोड़ तक ही पहुंची है।'

'मुख्यमंत्री कार्यालय के एक अधिकारी ने पुष्टि की कि आदित्यनाथ ने पार्टी कार्यकर्ताओं को लापरवाही से बचने की चेतावनी दी है और कहा है कि वे पूरी प्रक्रिया पर करीबी से नज़र रखे हुए हैं। अधिकारी ने बताया कि दो हफ्ते पहले हुई एक बंद कमरे की बैठक में भी मुख्यमंत्री ने ऐसी ही चिंता जताई थी। आदित्यनाथ ने मंत्रियों और विधायकों से इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होने को कहा और शादियों जैसे कार्यक्रमों के लिए यात्रा से बचने को कहा। नेता इस मुद्दे को हल्के में ले रहे हैं, जबकि यह वास्तव में एक गंभीर मामला है।'

राज्य निर्वाचन आयोग के 10 दिसंबर तक के आंकड़ों के अनुसार, यूपी की मौजूदा मतदाता सूची (दिनांक 27 अक्टूबर 2025) में 15.44 करोड़ मतदाता थे। SIR के लिए बूथ-स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) ने 15.43 करोड़ मतदाताओं को गणना फॉर्म बांटे, जो कुल मतदाताओं का 99.9 प्रतिशत है। इनमें से 80.29 प्रतिशत फॉर्म बीएलओ ने वापस ले लिए, जिन पर मतदाता या परिवार के किसी सदस्य के हस्ताक्षर थे। चुनाव आयोग ने बताया कि बाकी 19 प्रतिशत फॉर्म यानी 2.91 करोड़ 'एकत्र नहीं किए जा सके।' संशोधित मतदाता सूची अभी प्रकाशित नहीं हुई है। भाजपा के एक पदाधिकारी ने कहा कि लगभग पांचवां हिस्सा मतदाताओं का वोटर लिस्ट से हटना 'बेहद गंभीर' मामला है। 'बीएलए से मिली हमारी आंतरिक रिपोर्ट बताती है कि इन मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा उच्च जातियों से है, जो हमारा मुख्य आधार हैं। अगर इनमें से आधे भी उच्च जाति के हुए, तो हम कम से कम 1.5 करोड़ मतदाता खो सकते हैं। समय-सीमा में बहुत कम दिन बचे हैं, इसलिए यह बड़ी चिंता है।'

मुख्यमंत्री के अनुमान और चुनाव आयोग की गणना में अंतर पर उन्होंने कहा, 'चार करोड़ गायब मतदाताओं का मुख्यमंत्री का अनुमान भी सही है और लगभग तीन करोड़ का चुनाव आयोग का आंकड़ा भी सही है। फर्क सिर्फ इतना है कि मुख्यमंत्री ने संभवतः पहली बार वोट देने वाले मतदाताओं को भी इसमें शामिल किया है।' कई मतदाता शहरों में रहने के बजाय अपने पैतृक गांवों में ही अपना वोटर आईडी बनाए रखना चाहते हैं। इसमें ज्यादातर वे लोग शामिल हैं जिनका नाम दो जगह दर्ज है। इनकी संख्या लाखों में हो सकती है और इससे शहरी इलाकों में नुकसान हो सकता है, जहां हमारी मजबूत पकड़ है।'

2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने राज्य के ज्यादातर शहरी क्षेत्रों में जीत हासिल की थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में, भले ही 2019 के मुकाबले यूपी में पार्टी की सीटें लगभग आधी रह गईं, लेकिन राज्य के प्रमुख शहरी इलाकों में बीजेपी ने जीत दर्ज की। जहां बीजेपी के वरिष्ठ नेता सरकारी कार्यक्रमों, निजी आयोजनों और पार्टी कार्यक्रमों में व्यस्त हैं, वहीं विपक्षी नेता पूरी तरह SIR पर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपने मुख्य वोटर आधार की चिंता है। वे अनजाने में अपनी संगठनात्मक क्षमता मजबूत कर रहे हैं। चुनाव आयोग के आंकड़े भी इस बात की पुष्टि करते हैं। यूपी में राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त किए गए 4.91 लाख बीएलए में से 1.59 लाख बीजेपी के हैं, इसके बाद समाजवादी पार्टी के 1.42 लाख हैं। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के 1.38 लाख बीएलए हैं, जबकि कांग्रेस के 49,121 हैं।

'इस पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता उदयवीर सिंह ने बताया कि मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया की निगरानी करना 'कुछ हद तक परेशान करने वाला' रहा है, लेकिन इससे पार्टी को फायदा हुआ है। अब हमारे कार्यकर्ता हर बूथ पर हैं। बिहार में जिस तरह की अफरा-तफरी देखी गई, उसके बाद अब यूपी के लोग ज्यादा जागरूक हो गए हैं और इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं।'

पश्चिमी यूपी से बीजेपी नेता अवनीश त्यागी ने कहा, 'हमें SIR प्रक्रिया पर कहीं ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। हमारे कार्यकर्ताओं को जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास में नहीं रहना चाहिए। 'बीजेपी ने राज्य के दोनों उपमुख्यमंत्रियों केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को 25-25 जिलों की विशेष जिम्मेदारी सौंपी है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को पुलिस और जिला प्रशासन के साथ मिलकर घर-घर जाकर सत्यापन करने के निर्देश दिए हैं, जिनमें झुग्गी बस्तियां और अन्य इलाके भी शामिल हैं। जो लोग वैध दस्तावेज पेश नहीं कर पा रहे हैं, उनकी जानकारी तुरंत प्रशासन को दी जाए।'

(दि प्रिंट हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

दुनिया खड़ी कर रही दीवारें भारत बुन रहा है नए रिश्ते

- मुक्त व्यापार समझौतों से घट रहा घाटा और बढ़ रहा भरोसा

भारत ने 2025 में अपनी आर्थिक तरक्की को किया मजबूत

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत ने 2025 में अपनी आर्थिक तरक्की को मजबूत किया है। वैश्विक स्तर पर बदलते समीकरणों और संरक्षणवादी व्यापार नीतियों के बावजूद ऐसा हुआ है। यह सफलता मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) और देश के भीतर किए गए बड़े सुधारों का नतीजा है। इनके बूते भारत ने तरक्की की रफ्तार पर आंच नहीं आने दी है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, नवंबर 2025 में भारत के कुल निर्यात में पिछले साल की तुलना में 15.52 फीसदी की ग्रोथ हुई। यह

73.99 अरब डॉलर तक पहुंच गया। वहीं, कुल आयात लगभग 80.63 अरब डॉलर पर स्थिर रहा। इसके चलते घाटे में 61 फीसदी की कमी आई।

ताबड़तोड़ सुधारों से मिली मदद

घरेलू स्तर पर 22 सितंबर 2025 से प्रभावी नेक्स्ट जेन जीएसटी 2.0 सुधारों ने निर्यातकों के लिए टैक्स परिदृश्य को मौलिक रूप से बदल दिया है। टैक्स स्लैब को एक सरलीकृत संरचना में समेकित करके सरकार ने अनुपालन की जटिलता को कम किया है। कपड़ा और पैकेजिंग जैसे आवश्यक क्षेत्रों के लिए उत्पादन लागत को घटाया है। इन सुधारों की एक प्रमुख विशेषता शून्य–रेटेड सप्लाई के लिए 90 फीसदी का प्रोविजनल रीफंड है, जो यह सुनिश्चित करती है कि निर्यातकों के पास स्वस्थ नकदी प्रवाह बना रहे और उन्हें उन लंबी देरी का सामना न करना पड़े जो पहले छोटे व्यवसायों को बाधित करती थीं। इन टैक्स बदलावों के पूरक के रूप में चार एकीकृत श्रम संहिताओं को लागू किया गया है। इन्होंने 29 औपनिवेशिक–युग के कानूनों को एक आधुनिक ढांचे में सुव्यवस्थित किया है। ये संहिताएं निर्यातकों को वैश्विक मांग में उतार–चढ़ाव का जवाब देने के लिए आवश्यक लचीलापन प्रदान करती हैं।

अब बॉर्डर से सटे एयरबेस पर तैनात होंगे अपाचे हेलीकॉप्टर

- राजस्थान के जैसलमेर में हुए 2 युद्धाभ्यास में थे शामिल
- बेहद खतरनाक, एक साथ 256 टारगेट कर सकते हैं ट्रैक

जैसलमेर (एजेंसी)। भारतीय सेना ने दुनिया के सबसे घातक अटैक हेलीकॉप्टर कहे जाने वाले एएच-64ए अपाचे अटैक हेलीकॉप्टरों को जोधपुर एयरबेस पर तैनात किया है, जो एक समय में 256 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है और 16 लक्ष्यों को प्राथमिकता दे सकता है। ये हेलीकॉप्टर अब पाकिस्तान सीमा की निगरानी और भारत की रक्षात्मक और आक्रामक क्षमताओं को मजबूत बनाएंगे। हाल ही में जैसलमेर क्षेत्र में हुए सैन्य अभ्यास 'त्रिशूल' और 'मरु ज्वाला' में इन हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया गया था। अभ्यास के बाद इन्हें पश्चिमी सीमा के पास एक महत्वपूर्ण एयरबेस पर तैनात किया गया है। यह पहली बार है जब भारतीय थल सेना के अपाचे हेलीकॉप्टरों ने किसी बड़े सैन्य अभ्यास में हिस्सा लिया। अभ्यास के दौरान इन हेलीकॉप्टरों ने तय लक्ष्यों पर सटीक हमला किया। जून 2025 में अमेरिका से मिले 3 अपाचे हेलीकॉप्टरों की पहली खेप की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है।

मुख्यमंत्री ने म. प्र. आई.ए.एस. एसोसिएशन सर्विस मीट 2025 का शुभारंभ किया

भारत अब हर चुनौती और परिस्थिति का सामना करने में सक्षम : सीएम यादव

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि स्वामी विवेकानंद का विचार था कि 21वीं सदी भारत की होगी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के प्रभावी नेतृत्व और मार्गदर्शन में आज विवेकानंद जी का यह स्वप्न साकार होता दिख रहा है। वर्तमान में विश्व का हर देश भारत से मित्रता करना चाहता है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में भारत अब हर चुनौती और परिस्थिति का सामना करने में सक्षम है। भारतीय

- **आईएएस अधिकारी हर चुनौती का सामना करते हुए देश को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं**

प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की भूमिका के आधार पर ही भारत आज दुनिया के सामने मजबूती से खड़ा है। हमारे प्रशासनिक अधिकारी हर चुनौती का सामना करते हुए देश को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। भारत की अनेक विविधताओं के बीच आज देश में यह सेवा क्षेत्र मजबूती और प्रतिबद्धता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव म.प्र. आई.ए.एस. एसोसिएशन सर्विस मीट-2025 के शुभारंभ अवसर पर प्रशासन अकादमी में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कार्यक्रम का दीप प्रज्जवलित कर शुभारंभ किया। शुभारंभ अवसर पर मुख्य

सचिव श्री अनुराग जैन, सेवानिवृत्त अधिकारियों सहित मध्यप्रदेश कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव को इस अवसर पर स्मृति चिन्ह भी भेंट किया गया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि देश की आजादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों के फलस्वरूप प्रशासनिक व्यवस्था निर्मित हो पाई। देश में राजाओं की सत्ता को प्रजातंत्र में बदलने में प्रशासनिक अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। हमारे देश की संवैधानिक व्यवस्था में संघीय प्रणाली है और इस बीच प्रदेश के अधिकारियों ने केंद्र-राज्यों के साथ समन्वय करते हुए राज्य की बेहतर छवि बनाई है। मध्यप्रदेश एक प्रयोगशाला की तरह है, जहां कई क्षेत्रों में लगातार नवाचार हुए और इनमें से कई नवाचारों का देश-दुनिया में अनुसरण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी योग्यता और अनुभव के महत्व को पहचानते हैं। इसी का परिणाम है कि सेवाकाल के बाद भी कई अधिकारियों के अनुभव का लाभ शासन व्यवस्था को मिल रहा है। प्रदेश के सभी प्रशासनिक अधिकारी सम्मान के हकदार हैं। प्रसन्नता का विषय है कि सभी अधिकारी एक परिवार की तरह हर कठिनाई से निकलने का मार्ग प्रशस्त करते हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में अनुभव से भरे हमारे वरिष्ठ अधिकारी और ऊर्जा से भरे हमारे युवा साथी विकसित और आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के आधार हैं। उन्होंने कहा कि यह समय नीतियां बनाने और योजनाओं का क्रियान्वयन करने के साथ नवाचार को समझने, तकनीक को अपनाने और नागरिक की दृष्टि से सोचने का भी है। हमें सेवा कर पाने का अवसर सौभाग्य से मिलता है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों ने यह सौभाग्य अपने कठिन परिश्रम से अर्जित किया है। हमारी संस्कृति में नर सेवा को नारायण सेवा माना गया है। आम आदमी के कष्टों का समाधान करने, उनकी समस्याओं की सुनवाई करने और सार्थक समाधान देने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमें प्रदेश के विकास के लिए अपना शत-प्रतिशत देने का संकल्प लेना होगा।

मध्यप्रदेश ऐसा राज्य है, जो सभी को अपनाता है

मध्यप्रदेश आईएएस एसोसिएशन के अध्यक्ष एसीएस मनु श्रीवास्तव ने कहा कि सर्विस मीट में नए वेंचर्स की सफलता पर विमर्श किया जाएगा। मध्यप्रदेश ऐसा राज्य है, जो सभी को अपना लेता है। प्रदेश के आईएएस अफसर मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर सेवाएं दे रहे हैं। मध्यप्रदेश आईएएस एसोसिएशन एक परिवार की तरह है। आयोजन समिति के अध्यक्ष पी. नरहरि ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में राज्य में सेवा का कार्य पूर्ण गरिमा के साथ किया जा रहा है।

एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम में लगातार 2 तिमाहियों से मध्यप्रदेश प्रथम

- यह उपलब्धि प्रदेश के स्वास्थ्य तंत्र की प्रतिबद्धता, समर्पण और टीमवर्क का प्रतिफल : शुक्ल
- वर्ष 2025-26 में 70 लाख से अधिक बच्चों और 9 लाख 42 हज़ार गर्भवती महिलाओं के जाँच की गयी
- 45 लाख महिलाओं एवं बच्चों को प्रदान किया गया चिकित्सकीय उपचार

भोपाल। मध्य प्रदेश में एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों एवं महिलाओं में खून की कमी को दूर करने के लिए निरंतर और समन्वित प्रयास किए जा रहे हैं। एनीमिया मुक्त होने का अर्थ है कि बच्चों और महिलाओं के शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर सामान्य हो, जिससे उनका शारीरिक एवं मानसिक विकास बेहतर हो सके। यह कार्यक्रम मातृ एवं बाल स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में स्थापित हुआ है। प्रदेश में किए गए सतत और प्रभावी प्रयासों का सकारात्मक परिणाम यह रहा कि एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार की एचएमआईएस रैंकिंग में मध्य प्रदेश ने लगातार पिछली दो तिमाहियों में देशभर में प्रथम स्थान प्राप्त किया।

उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि यह उपलब्धि प्रदेश के स्वास्थ्य तंत्र की प्रतिबद्धता, समर्पण और टीमवर्क का प्रतिफल है। उन्होंने अभियान से जुड़े समस्त चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ, एएनएम, आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं मैदानी अमले की सराहना करते हुए कहा कि इनके अथक परिश्रम, संवेदनशीलता और सेवा भाव के कारण ही इतने व्यापक स्तर पर जांच, उपचार और जागरूकता संभव हो पाई है। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने सभी स्वास्थ्यकर्मियों को बधाई देते हुए अपेक्षा व्यक्त की कि वे इसी समर्पण के साथ कार्य करते हुए प्रदेश को पूर्ण रूप से एनीमिया मुक्त बनाने के लक्ष्य की ओर निरंतर अग्रसर रहेंगे।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान प्रदेश में दस्तक अभियान के प्रथम चरण का संचालन 22 जुलाई से 16 सितम्बर 2025 तक किया गया। इस अवधि में 6 माह से 59 माह तक के कुल 70.62 लाख बच्चों में डिजिटल हीमोग्लोबिनो मीटर के माध्यम से हीमोग्लोबिन की जांच सुनिश्चित की गई। जांच के पश्चात लगभग 35.21 लाख अल्प एवं मध्यम एनीमिक बच्चों को आवश्यक चिकित्सकीय उपचार प्रदान किया गया, जबकि 3,575 गंभीर एनीमिया से ग्रस्त बच्चों को चिन्हांकित कर जिला स्तर पर रक्ताधान अथवा यथोचित प्रबंधन सुनिश्चित किया गया।

-अभियान के अंतर्गत प्रदेश की 9.42 लाख गर्भवती महिलाओं की एनीमिया जांच की गई। जांच के दौरान 3.02 लाख मध्यम से गंभीर तथा 10,660 अतिगंभीर एनीमिक महिलाओं को चिन्हांकित किया गया, जिन्हें आयरन एवं फोलिक एसिड (आई.एफ.ए.), आयरन सुक्रोश, एफ.सी.एम. तथा आवश्यकता अनुसार रक्ताधान के माध्यम से उपचारित किया गया। इन प्रयासों से गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार के साथ-साथ सुरक्षित मातृत्व को भी बढ़ावा मिला है।

एनीमिया की रोकथाम एवं उपचार के लिए प्रदेश में अपनाई गई बहुआयामी रणनीति

एनीमिया की रोकथाम एवं उपचार के लिए प्रदेश में बहुआयामी रणनीति अपनाई गई है, जिसमें आयरन और फोलिक एसिड की गोलियों एवं सिरप का नियमित वितरण, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं की नियमित स्वास्थ्य जांच, बच्चों में कृमि नियंत्रण (डिवॉर्मिंग) अभियान, पोषण युक्त आहार को बढ़ावा, किशोरियों के लिए साप्ताहिक आयरन सप्लीमेंटेशन, स्कूलों एवं आंगनवाड़ी केंद्रों में स्क्रीनिंग तथा पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता अभियानों का संचालन शामिल है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य विभाग द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग के समन्वय से सूचना एवं व्यापक प्रचार-प्रसार कर नागरिकों को जागरूक भी किया गया है। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा एनीमिया मुक्त भारत अभियान की शुरुआत वर्ष 2018 में राष्ट्रीय पोषण मिशन (पोषण अभियान) के अंतर्गत की गई थी। इस अभियान का वर्तमान लक्ष्य मातृ एवं बाल स्वास्थ्य में सुधार लाना तथा बच्चों और महिलाओं को एनीमिया मुक्त बनाना है। मध्य प्रदेश में किए जा रहे समर्पित प्रयास इस लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में एक मजबूत आधार प्रदान कर रहे हैं और एक स्वस्थ, सशक्त एवं सक्षम समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

भोपाल का तापमान

अधिकतम 27 °c

न्यूनतम 23°c

सुबह सवेरे

भोपाल ■ शनिवार, 20 दिसंबर 2025

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रहे अपनी सेना

नई दिल्ली (एजेंसी)। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत का स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम 'सुदर्शन चक्र' देश की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दिल्ली में आयोजित एयर फोर्स कमांडर्स कॉन्क्लेव में गुरुवार को रक्षा मंत्री ने भाग लिया। उन्होंने वायुसेना के शीर्ष अधिकारियों से कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से मिले रणनीतिक और ऑपरेशनल संबंधी सबक को ध्यान में रखकर भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रहें। रक्षा मंत्री ने वायुसेना को तकनीकी रूप से उन्नत, रणनीतिक रूप से आत्मविश्वासी और हर परिस्थिति में प्रभावी प्रतिक्रिया देने वाली फोर्स बताया।

राजनाथ बोले-

ऑपरेशन सिंदूर को ध्यान में रखकर बनाएं प्लान

कॉन्क्लेव में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

जब पाकिस्तान ने भारतीय ठिकानों को निशाना बनाने की असफल कोशिश की, तब आम लोग शांत रहे और सामान्य गतिविधियां जारी रहीं। यह भारतीय जनता के अपनी सेनाओं पर भरोसे को दिखाता है। ऐसी स्थिति में लोगों का संयम देश की तैयारी और क्षमता पर विश्वास को दर्शाता है। रूस-यूक्रेन युद्ध, इजराइल-हमास संघर्ष, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर से स्पष्ट है कि आधुनिक युद्ध में एयर पावर केवल सामरिक नहीं, बल्कि रणनीतिक साधन बन चुकी है। इसकी ताकत गति, आश्चर्य और त्वरित प्रभाव में है, जिससे राजनीतिक नेतृत्व को भी स्पष्ट संदेश देने में मदद मिलती है।

कहा-

सुदर्शन चक्र से मजूबत होगी देश की सुरक्षा

'जी-राम-जी' बिल का विरोध, टीएमसी का रातभर धरना

नई दिल्ली (एजेंसी)। संसद में गुरुवार रात 12.30 बजे राज्यसभा से वीबी-जी राम जी बिल पास हो गया। हालांकि विपक्षी सांसदों ने बहस के दौरान जमकर हंगामा किया। बिल के पास होने से पहले सांसद राज्यसभा से वॉकआउट कर गए। विपक्ष की मांग थी कि बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास

भेजा जाए। हालांकि सदन में विपक्ष की गैरमौजूदगी के बीच बिल ध्वनिमत से पास कर दिया गया। बिल के विरोध में तृणमूल सांसद, संसद के मकर द्वार पर रातभर से धरने पर बैठे हैं। इनका कहना है कि ये बिल महात्मा गांधी का अपमान है और किसानों-गरीबों के खिलाफ है।

तमिलनाडु-गुजरात में एसआईआर की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होगी

चेन्नई/गांधीनगर (एजेंसी)। चुनाव आयोग शुक्रवार को तमिलनाडु और गुजरात में कराए गए स्पेशल इंटेसिव रिवीजन (एसआईआर, सामान्य शब्दों में वोटर वेरिफिकेशन) की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी करेगा। इसके बाद मतदाता लिस्ट में अपने नाम

चेक कर सकेंगे। इससे पहले चुनाव आयोग ने 16 दिसंबर को पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गोवा, लक्षद्वीप और पुडुचेरी की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की थी। आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 27 अक्टूबर को एसआईआर की घोषणा के समय इन राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में 13.35 करोड़ मतदाता थे। वहीं ड्राफ्ट लिस्ट में यह संख्या घटकर 12.33 करोड़ रह गई है। यानी 1.02 करोड़ नाम हटाए गए हैं।

यूपी में नए साल में मिलेंगी 1.5 लाख सरकारी नौकरियां

लखनऊ (एजेंसी)। यूपी की योगी सरकार नए साल में युवाओं को बड़ा तोहफा देने जा रही है। 2026 में डेढ़ लाख सरकारी नौकरियां निकलेंगी। सीएम योगी ने हाल ही में अफसरों के साथ बैठक में विभागवार खाली पदों की डिटेल मांगी थी, जिससे

इन पदों पर नियुक्ति की जा सके। इसकी समीक्षा करने के बाद 2026 में युवाओं को 1.5 लाख सरकारी नौकरी देने की इजाजत दे दी। ये नौकरियां शिक्षा, राजस्व, आवास विकास और पुलिस समेत प्रदेश अलग-अलग विभागों में दी जाएंगी। सबसे ज्यादा भर्तियां पुलिस और शिक्षा विभाग में होंगी। ये भर्तियां होने के साथ ही साल-2026 में योगी सरकार के नाम सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी देने का रिकॉर्ड दर्ज हो जाएगा।

अब 80 किलोमीटर की स्पीड से पार कर सकेंगे टोल

रुकना भी नहीं होगा, गडकरी ने बताया-कब से होगा शुरू

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में बताया कि सैटेलाइट-आधारित टोल कलेक्शन सिस्टम 2026 के आखिर तक पूरे देश में चालू हो जाएगा, जिससे यात्रियों को टोल प्लाजा पर इंतजार नहीं करना पड़ेगा और सरकार को ज्यादा रेवेन्यू मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस नई तकनीक से 80 की स्पीड से लोग टोल पार कर सकेंगे और उन्हें वहां रुकना भी नहीं होगा।

प्रश्नकाल के दौरान सप्लीमेंट्री सवालों का जवाब देते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने कहा कि नई टेक्नोलॉजी सैटेलाइट और एआई-आधारित होगी और यात्रियों को टोल प्लाजा पर इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इससे 1,500 करोड़ रुपये के फ्यूल की बचत होगी और सरकार के रेवेन्यू में 6,000 करोड़ रुपये जुड़ेंगे और टोल प्लाजा पर इंतजार का समय जीरो हो जाएगा। उन्होंने सदन में कहा, मल्टी-लेन फ्री फ्लो टोल एक बहुत अच्छी सुविधा है। पहले, हमें टोल पर पेमेंट करना पड़ता था, और इसमें 3 से 10 मिनट लगते थे; फिर फास्टैग की वजह से, समय घटकर 60 सेकंड या उससे कम हो गया है। हमारी इनकम कम से कम 5,000 करोड़ रुपये बढ़ गई है।

फास्टैग की जगह नया नियम आने के बाद, कारें अब ज्यादा से ज्यादा 80 किमी प्रति घंटे की स्पीड से टोल पार कर सकती हैं, और किसी को भी टोल पर रोका नहीं जाएगा। उन्होंने आगे कहा, हमारा मकसद इसे जीरो मिनट तक लाना है, और इसमें एआई और फास्टैग के साथ सैटेलाइट के ज़रिए नंबर प्लेट पहचान शामिल होगी। गडकरी ने कहा, 2026 के आखिर तक हम यह काम 100 परसेंट पूरा कर लेंगे, और एक बार यह काम पूरा हो जाने के बाद, हमारी इनकम से 1,500 करोड़ रुपये की बचत होगी, और हमारी इनकम में 6,000 करोड़ रुपये की और बढ़ोतरी होगी, और टोल चोरी खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा कि नई टेक्नोलॉजी से लोगों को निश्चित रूप से मदद मिलेगी, और यात्रा का समय निश्चित रूप से कम होगा।

प्रदेश के कई जिलों में घना कोहरा

विजिबिलिटी बेहद कम, दिल्ली रूट की ट्रेनें 5 घंटे तक लेट, उड़ानों पर भी असर

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश में ठंड का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार सुबह भी प्रदेश के कई जिलों में घना कोहरा छाया रहा, जिससे दृश्यता काफी कम हो गई। ग्वालियर में गुरुवार रात से ही कोहरा बना हुआ है और शुक्रवार सुबह 9 बजे तक हालात नहीं सुधरे। बीते दिन यहां अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे ठंड में अचानक बढ़ोतरी महसूस की गई।

घने कोहरे का सबसे ज्यादा असर रीवा में देखने को मिला, जहां 50 मीटर के बाद कुछ भी साफ नजर नहीं आया। दतिया और सागर में दृश्यता 200 से 500 मीटर, जबकि ग्वालियर, सतना, जबलपुर और नौगांव में 500 से 1 हजार मीटर के बीच रही। इंदौर, मंडला और खजुराहो में विजिबिलिटी 1 से 2 किलोमीटर दर्ज की गई। भोपाल, उज्जैन, राजगढ़, दमोह और उमरिया में 2 से 4 किलोमीटर तक दृश्यता रही।

राजधानी भोपाल में सुबह से ही कोहरे का असर बना रहा। शहर के कई इलाकों में दृश्यता कम रही, जिससे लोगों को सर्द हवाओं के साथ ठंड का ज्यादा अहसास हुआ।

इंदौर का पारा 4.1 डिग्री, शिवपुरी सबसे ठंडा- गुरुवार-शुक्रवार की रात के न्यूनतम तापमान की बात करें तो इंदौर 4.1 डिग्री सेल्सियस के साथ बड़े शहरों में सबसे ठंडा रहा। वहीं प्रदेश में शिवपुरी सबसे ठंडा जिला रहा, जहां पारा 4 डिग्री तक गिर गया। राजगढ़ में 5 डिग्री, पचमढ़ी में 5.6, मलाजखंड में 6.8, रायसेन में 7.4 और मंडला में 7.7 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।

मौसम विभाग का अलर्ट- मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले सात दिनों तक प्रदेश में इसी तरह का मौसम बना रहेगा। सुबह-शाम घना कोहरा छाने की संभावना है और ठंड का असर और तेज हो सकता है। लोगों को सतर्क रहने और आवश्यक सावधानियां बरतने की सलाह दी गई है।

महुआ के खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं करेगी सीबीआई

- दिल्ली हाईकोर्ट ने लोकपाल का आदेश रद्द किया

नई दिल्ली (एजेंसी)। पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में सीबीआई फिलहाल टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं करेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने

शुक्रवार को लोकपाल की ओर से चार्जशीट फाइल करने की मंजूरी को रद्द कर दिया है। जस्टिस अनिल क्षतरपाल और हरीश वैद्यनाथन शंकर की बेंच ने लोकपाल से कहा है कि वह लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम की धारा 20 के तहत एक महीने के भीतर कानून के अनुसार दोबारा फैसला करे। सुनवाई के दौरान महुआ मोइत्रा के वकील ने दलील दी कि लोकपाल ने मंजूरी देते समय कानूनी प्रक्रिया का सही तरीके से पालन नहीं किया। कानून के मुताबिक उनकी टिप्पणी लेना जरूरी होता है।

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

पिता की वसीयत सर्वोपरि

- समुदाय से बाहर शादी पर बेटी को संपत्ति में हिस्सा नहीं

नई दिल्ली (एजेंसी)। लैंगिक समानता के कई ऐतिहासिक फैसलों के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने एक पिता की वसीयत को बरकरार रखते हुए बेटी को संपत्ति से बेदखल कर दिया है। पिता एन एस श्रीधरन ने अपनी नौ संतानों में से एक बेटी शाइला जोसेफ को अपनी वसीयत में जायदात से इसलिए बेदखल कर दिया था क्योंकि उसने अपनी बिरादरी के बाहर शादी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट के उन फैसलों को पलट दिया है, जिसमें वसीहत पर संदेह जताते हुए संपत्ति को नौ बच्चों में बराबर बांटने का आदेश जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के

दौरान जस्टिस अहसनुद्दीन अमानुल्लाह और के विनोद चंद्रन की बेंच ने कहा कि वसीयत को चुनौती नहीं दी जा सकती क्योंकि वह स्पष्ट रूप से साबित हो चुकी है। बेंच ने कहा, वसीयत में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, जो स्पष्ट रूप से साबित हो चुकी है। हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट के फैसले और डिक्री को रद्द किया जाता है। वादी (शाइला) को अपने पिता की संपत्ति पर कोई दावा नहीं मिलता, जिसे वसीयत द्वारा अन्य भाई-बहनों को दे दिया गया है।

वसीयत के मामले में नहीं लागू होता समझदारी का नियम

सुप्रीम कोर्ट ने यह कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि वसीयत के मामलों में समझदारी का नियम लागू नहीं होता। वसीयत व्यक्ति की अपनी इच्छा होती है और उसे अपनी संपत्ति बांटने का पूरा अधिकार होता है। अगर वसीयत के जरिए सभी भाई-बहनों को उनकी विरासत से वंचित किया गया होता, तब अदालतें समझदारी का नियम लागू कर सकती थीं। सुप्रीम कोर्ट ने शाइला को वसीयत से बेदखल करने के कारण पर भी टिप्पणी की। बेंच ने कहा, इस बहिष्कार का एक कारण बताया गया है।

अगली बार नकाब को हाथ लगाया तो सबक सिखाएंगे

- हिजाब विवाद पर नीतिश को महबूबा की बेटी की धमकी

श्रीनगर (एजेंसी)। बिहार में एक महिला डॉक्टर का हिजाब हटाने को लेकर मुख्यमंत्री नीतिश कुमार की दूसरे राज्यों में भी आलोचना हो रही है। जम्मू-कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती

की बेटी और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने शुक्रवार को बिहार सीएम के खिलाफ श्रीनगर में एफआईआर दर्ज कराई। इल्तिजा मुफ्ती ने मीडिया से बात करते हुए नीतिश कुमार को चेतावनी दी और कहा- आपको (नीतिश) कोई हक नहीं बनता कि आप हमारे नकाब या हिजाब को हाथ लगाए। अगली बार आपने हमारे हिजाब को हाथ लगाया तो हम मुसलमान औरतें आपको ऐसा सबक सिखाएंगी कि जिंदगी भर भूलेंगे नहीं। इल्तिजा ने कहा-यह हरकत बर्दाश्त से बाहर है।

बांग्लादेश में फिर भड़की हिंसा, हालात बेकाबू

- 2 न्यूज चैनल्स और अवामी लीग के ऑफिस फूंके, जमकर किया उत्पात

ढाका (एजेंसी)। बांग्लादेश में शेख हसीना के विरोधी नेता उस्मान हादी की मौत के बाद हिंसा भड़क गई है। प्रदर्शनकारियों ने गुरुवार देर रात देश के सबसे बड़े अखबार डेली स्टार और प्रोथोम आलो के ऑफिस में जबरन घुसकर तोड़फोड़ और आगजनी की। इसके अलावा पूर्व राष्ट्रपति शेख मुजीबुर्रहमान के आवास में भी तोड़फोड़ की गई है और शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के ऑफिस को भी जला दिया गया है। उस्मान हादी शेख हसीना के खिलाफ जुलाई 2024 में हुए छात्र आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से

एक थे। उन्हें 12 दिसंबर को चुनाव प्रचार के दौरान सिर में गोली मारी गई थी। इसके बाद उन्हें बेहतर उपचार के लिए सिंगापुर ले जाया गया था। 6 दिन बाद उनकी मौत हो गई। बीबीसी बांग्ला की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में धर्म का अपमान करने के आरोप में एक हिंदू युवक को पीट-पीटकर मार डाला। इसके बाद उसके शव को नग्न करके एक पेड़ से लटका कर आग लगा दी। पुलिस ने मृतक की पहचान दीपू चंद्र दास के रूप में की है पुलिस ने बताया कि यह घटना गुरुवार रात भालुका में हुई। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें लोग 'अल्लाह-हू-अकबर' के नारे लगाते दिख रहे हैं। बांग्लादेश एक बार फिर हिंसा की आग में जल उठा है। शेख हसीना और भारत विरोधी नेता उस्मान हादी की मौत के बाद पूरे बांग्लादेश में आक्रोश है। प्रदर्शनकारियों ने डेली स्टार और प्रोथोम अलो अखबारों के ऑफिस में घुसकर आग लगा दी और जमकर तोड़फोड़ की।

- शेख हसीना विरोधी नेता की मौत के बाद हिंसा

हिंदू युवक को जलाया

50 साल बाद मिलेंगे सहपाठियों से शिवराज सिंह चौहान

माडल स्कूल में 21 दिसम्बर को गोल्डन जुवली सेलिब्रेशन का कार्यक्रम

भोपाल। मॉडल स्कूल टीटी नगर में दिनांक 21 तारीख को 1975 बैच में जिन विद्यार्थियों ने हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण की थी उन विद्यार्थियों की गोल्डन जुवली सेलिब्रेशन का कार्यक्रम मॉडल स्कूल टीटी नगर में रखा गया। इस अवसर पर पूर्व विद्यार्थी रहे शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री, पूर्व पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी, पूर्व डीआरएम ,एस पी त्रिवेदी और कई जानी मानी हस्तियां इस गोल्डन सेलिब्रेशन प्रोग्राम में शामिल होने के लिए भोपाल पधार रहे हैं । कुछ विद्यार्थी विदेश से और कुछ विद्यार्थी पूरे भारतवर्ष के प्रांतों से यहां पर उपस्थित हो रहे हैं।

दो दिवसीय पूर्व छात्रों का मिलन समारोह का कार्यक्रम 20 तारीख को मयूरी गार्डन में भदभदा पर रखा गया है जो दिन भर चलेगा और 21.12.25 तारीख को प्रातः9.45 बजे मॉडल स्कूल टीटी नगर में रखा गया। उक्त आशा की जानकारी समिति के संयोजक अजय श्रीवास्तव नीलू,एस पी त्रिवेदी, शेखर दुबे,पकंज कुलश्रेष्ठ आलोक चतुर्वेदी, प्रवीण वरगले,हुए बताया इस अवसर पर सबको सम्मानित भी किया जाएगा, और एक स्मारिका का प्रकाशन भी किया जा रहा है जिसमें सभी 1975 बेचकर के विद्यार्थियों की पारिवारिक जानकारियां भेज दी जा रही हैं।

युवक ने खुद का गला रेता, मौत

आखिरी बार मां से कहा था, मेरी नासा वाली गर्लफ्रेंड बुला रही है

भोपाल (नप्र)। भोपाल के नेहरू नगर में रहने वाले युवक ने गुरुवार रात को खुद का गला रेत लिया। शुक्रवार सुबह इलाज के दौरान हमीदिया अस्पताल में उसकी मौत हो गई। सुसाइड के प्रयास के पहले उसने मां से आखिरी बातचीत में कहा था कि मेरी नासा वाली गर्लफ्रेंड बुला रही है। मैं उसके साथ अंतरिक्ष में जाना चाहता हूं। परिजनों का कहना है कि युवक का मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ था। अलग-अलग मनो चिकित्सक उसका इलाज कर चुके हैं। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के मुताबिक 45 वर्षीय आयुष मेहता नेहरू नगर में रहता था और एमबीए करने के बाद घर में रहता था। उसके पिता इंजीनियर थे और प्राइवेट ठेकेदारी करते थे। उनकी मौत हो चुकी है। आयुष का मानसिक संतुलन साल 2002 से बिगड़ा हुआ था। आए दिन बहकी हुई बातें करता था। शादी कराने के लिए मां के साथ विवाद करता था। पूर्व में भी वह गला रेतकर सुसाइड का प्रयास कर चुका है। शुक्रवार दोपहर को पुलिस ने पीएम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। मामले की सभी एंगल पर जांच की जा रही है।

बेडरूम में सब्जी काटने की छुरी से रेता गला- उस समय परिजनों ने समय रहते उसे अस्पताल पहुंचा दिया था। जिससे उसकी जान बच गई थी, लेकिन गुरुवार रात करीब दस बजे आयुष ने अपने कमरे में सब्जी काटने वाली छुरी से स्वयं का गला रेत लिया। मां ने परिजनों और पुलिस को मदद के लिए बुलाया। तत्काल बेटे को परिजनों के साथ अस्पताल लेकर पहुंची, जहां इलाज के दौरान बेटे की मौत हो गई।

मां से करता था मारपीट- मृतक के केयर टेकर मनीष चौहान ने बताया कि लंबे समय से युवक का मानसिक संतुलन खराब था। आए दिन मां को पीटता था। बहकी हुई बातें करता था, अमेरिका ले जाने और नासा ले जाने की बातें करता था। कई बार डॉक्टरों से भी बदसलूकी कर चुका था। अक्टूबर में भी उसने गला रेतकर सुसाइड करने का प्रयास किया था। लेकिन तब उसकी जान बच गई थी।

सतना में संक्रमित रक्त चढ़ाने के प्रकरण में कड़ी कार्रवाई

ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर और लैब टेक्निशियन निलंबित

भोपाल (नप्र)। सतना जिले में संक्रमित रक्त चढ़ाने के गंभीर प्रकरण में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा कड़ी कार्रवाई की गई है। यह कार्रवाई सीईओ आयुष्मान भारत डॉ. योगेश भरसट की अध्यक्षता में गठित सात सदस्यीय जांच समिति की प्राथमिक जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई है। प्राथमिक जांच के निष्कर्षों के आधार पर जिला चिकित्सालय सतना के ब्लड बैंक प्रभारी डॉ. देवेन्द्र पटेल और दो लैब टेक्नीशियन श्री राम भाई त्रिपाठी तथा श्री नंदलाल पांडे को निलंबित किया गया है। इसके अतिरिक्त, जिला चिकित्सालय सतना के पूर्व सिविल सर्जन डॉ. मनोज शुक्ला को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। उन्हें जारी सूचना पत्र के संदर्भ में लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। स्पष्टीकरण समाधानकारक न होने की स्थिति में उनके विरुद्ध कड़ी विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। उल्लेखनीय है कि राज्य स्तरीय समिति का गठन डॉ. योगेश भरसट (आईएएस), संचालक, राज्य रक्ताधान परिषद की अध्यक्षता में दिनांक 16 दिसम्बर को किया गया था। समिति की प्रीलिमिनरी रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की गई है।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री पटेल ने बताई दो वर्ष की उपलब्धियाँ

सीएम के नेतृत्व में ग्रामीण क्षेत्र के विकास हेतु सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ उल्लेखनीय उपलब्धियाँ अर्जित कीं

भोपाल (नप्र)। पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा श्रम मंत्री श्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने आज मिंटो हाल में आयोजित पत्रकार वार्ता में विभाग की दो वर्ष की उपलब्धियों से मीडिया को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के विकास हेतु सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ उल्लेखनीय उपलब्धियाँ अर्जित की है। मध्य प्रदेश में श्रमिकों के हित में भी अनेक उल्लेखनीय कार्य हुए हैं।

मंत्री श्री प्रह्लाद पटेल द्वारा प्रेस वार्ता में बताए गए तथ्य इस प्रकार हैं प्रसन्नता का विषय है कि भारत की संसद ने विकसित भारत-रोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) विधेयक, 2025 (विकसित भारत- जी राम जी विधेयक, 2025) को पारित किया है। यह विधेयक मनरेगा में व्यापक वैधानिक बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है, जो ग्रामीण रोज़गार को विकसित भारत 2047 के दीर्घकालिक विजन के साथ संयोजित करेगा तथा जवाबदेही, बुनियादी ढांचे के परिणामों और आय सुरक्षा को सुदृढ़ करेगा।गांव के विकास के बिना प्रदेश और राष्ट्र के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती।

आज से भोपाल मेट्रो सिटी बन जाएगा

मेट्रो 3 मिनट में पहुंचा देगी, 20 रुपए से किराया शुरू, एक दिन में 17 ट्रिप रहेंगी

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल आज 20 दिसंबर से मेट्रो सिटी बन जाएगी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मेट्रो का उद्घाटन करेंगे। 6.22 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर मेट्रो में सवार होकर शहर को देखेंगे। अगले दिन 21 दिसंबर की सुबह 9 बजे से आम लोग भी मेट्रो की सवारी कर सकेंगे। एक दिन में मेट्रो सुभाष नगर से एम्स के बीच कुल 17 ट्रिप लगाएगी। 3 मिनट में एक से दूसरे स्टेशन पर पहुंचेगी और न्यूनतम किराया 20 रुपए होगा।

आईएएस संतोष वर्मा का नया वीडियो वायरल

बोले-जैसे 2016 में 'माई के लाल' बने थे, फिर बनना होगा

भोपाल (नप्र)। अजाक्स के सम्मेलन में हाईकोर्ट को एससी-एसटी वर्ग के युवाओं को सिविल जज न बनने के लिए जिम्मेदार बताने और ब्राह्मणों की बेटियों को लेकर विवादित बयान देने वाले आईएएस संतोष वर्मा का एक और वीडियो वायरल हो रहा है।

जिसमें वे समाज के लोगों से एक बार फिर माई का लाल बनने का आह्वान कर रहे हैं। इसी सम्मेलन में बयान देने वाली एक महिला आईएएस मीनाक्षी सिंह का बयान भी अब वायरल हो रहा है। जिसमें वे कह रही हैं कि जातिगत पहचान और जातिवादी होना आज के समय की सबसे बड़ी मांग है। उन्होंने कहा कि सवर्ण समाज के लोग पक्षपात करते हैं। यह जातिवादी मानसिकता हमारे लिए जरूरी है। 23 नवम्बर को राजधानी के अंबेडकर पार्क में हुए अजाक्स के सम्मेलन में ब्राह्मणों की बेटियों और हाईकोर्ट पर टिप्पणी करने वाले आईएएस संतोष कुमार वर्मा के नए वायरल वीडियो में वे कह रहे हैं कि साल 2016 में हमने जो ताकत दिखाई थी, वह एकदम अलग थी और उस ताकत के दिखाने के बाद हम माई के लाल बन गए थे। आज हमारी स्थिति वैसी बिल्कुल नहीं है। अब स्थिति बदल गई है। हमें हर तरह से तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए फिर वैसी ही ताकत दिखानी होगी।

भदभदा पुल से छलांग लगाकर युवक ने सुसाइड किया

वॉट्सएप स्टेटस पर लिखा- मर्जी से जान दे रहा हूं...भदभदा तालाब पर हूं

भोपाल (नप्र)। भोपाल के भदभदा ब्रिज से तालाब में छलांग लगाकर युवक ने सुसाइड कर लिया। छलांग लगाने से पहले उसने अपने वॉट्सऐप स्टेटस पर लिखा- मैं अपनी मर्जी से जान दे रहा हूं। किसी का कोई दबाव नहीं है। भदभदा पुल पर हूं। घटना गुरुवार की रात की है।

शुक्रवार की सुबह शव तलाशने के बाद पीएम के लिए भेजा गया। दोपहर को बॉडी का पीएम कराने के बाद शव परिजन को सौंप दिया गया। पुलिस मृतक की सीडीआर की जांच करेगी। पुलिस के मुताबिक 30 वर्षीय हेमंत राय नेहरू नगर में रहता था। शादी पार्टियों में वीडियोग्राफी करने का काम करता था।

इसी के साथ रातीबढ़ इलाके में नमकीन की दुकान का संचालन करता था। परिजन हेमंत की शादी के लिए लड़की तलाश कर रहे थे। परिवार में

उसने कभी किसी परेशानी का जिक्र भी नहीं किया और आखिरी पोस्ट में भी सुसाइड का कारण नहीं लिखा है।

लिहाजा आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस का कहना है कि परिजन के डिटेल बयानों और सीडीआर जांच के बाद ही आत्महत्या के कारणों का खुलासा हो सकेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग का नवाचार

महापौर-पार्षद का चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय लेखा के संबंध में ऑनलाइन सुनवाई

भोपाल (नप्र)। राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री मनोज श्रीवास्तव ने महापौर, अध्यक्ष एवं पार्षद का चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने के संबंध में वीडियो काफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई का नवाचार किया है। अब संबंधित अभ्यर्थियों को सुनवाई के लिये राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल नहीं आना पड़ता। सुनवाई प्रत्येक गुरूवार को होती है। इससे अभ्यर्थियों के समय और धन दोनों की बचत हुई है। पूर्व में ऐसे प्रकरणों की सुनवाई राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्यालय भोपाल में होती थी।

अब तक 411 अभ्यार्थियों की हुई सुनवाई- राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री श्रीवास्तव द्वारा फरवरी 2025 से अब तक व्ही.सी. के माध्यम से 411 अभ्यर्थियों की सुनवाई की जा चुकी है। भोपाल, खण्डवा, छिंदवाड़ा, मन्दसौर, धार, सतना, उमरिया, ग्वालियर, अलीराजपुर, राजगढ, नीमच, शाजापुर, डिण्डौरी, सागर एवं हरदा जिले के अभ्यार्थियों की सुनवाई की जा चुकी हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा 97 अभ्यर्थियो के निर्वाचन व्यय लेखे सुनवाई उपरांत एवं दस्तावेज प्रमाण के आधार पर मान्य किये गये। राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा 226 अभ्यर्थियो को व्ही.सी. के माध्यम से सुनवाई

उपरांत निरर्हित किया गया। अधिकतम पांच साल तक के लिये निरर्हित किये जाने का प्रावधान है।

अभ्यर्थी नियत तारीख प्रत्येक गुरुवार को सायंकाल 4:30 पीएम से 6:00पीएम तक जिला मुख्यालय के एन आई सी रूम से जुड़कर राज्य निर्वाचन आयुक्त की व्ही.सी. में सम्मिलित होकर अपना पक्ष रख सकते हैं। प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिये आयोग द्वारा जिले के उप जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। म.प्र. नगरपालिक निगम एवं मध्यप्रदेश नगर पालिक अधिनियम के तहत निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत किया जाना और लेखा दाखिल करने में असफलता पर निरर्हित घोषित किये जाने के प्रावधान हैं।

नैसर्गिक न्याय के आधार पर लेखा दाखिल करने में असफल अभ्यर्थियों को विलम्ब से लेखा दाखिल करने और विहित रीति में लेखा दाखिल नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को पक्ष समर्थन के लिए राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया जाता है।

मंत्री विजय शाह के खिलाफ महिला कांग्रेस का प्रदर्शन

प्रदेश अध्यक्ष रीना बौरासी के नेतृत्व में मंत्री का बंगला घेराव की थी तैयारी, पुलिस ने रोका

भोपाल (नप्र)। रतलाम में जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह द्वारा लाड़ली बहना योजना की लाभार्थी महिलाओं की जांच कराने के बयान का लगातार विरोध हो रहा है। मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रीना बौरासी के नेतृत्व में आज भोपाल में महिला कांग्रेस ने प्रदर्शन किया।

प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से मंत्री विजय शाह के बंगले का घेराव करने जा रही महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रेडक्रॉस चौराहे पर बैरिकेडिंग कर रोक लिया। इस दौरान महिला कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ धक्का-मुक्की भी हुई।

पुलिस ने गिरफ्तार किया, वापस पीसीसी छोड़ा- प्रदर्शनकारी महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रेडक्रॉस हॉस्पिटल के सामने से गिरफ्तार कर पुलिस वैन में भर लिया। थोड़ी देर बाद पुलिस वैन से ही महिला कांग्रेस नेत्रियों को पीसीसी छोड़ दिया।

कार्रवाई नहीं होती

इसलिए कर रहे अपमान: रीना- महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रीना बौरासी ने कहा- विजय शाह जो महिलाओं के लिए जो शब्द बार-बार निकालते हैं उसकी समझाइश देने के लिए हम और हमारी महिला कांग्रेस की बहनें उनके बंगले पर जा रहे थे। पिछले पांच दिनों से महिला कांग्रेस प्रदेश भर में उनके पुतले जला रही है, लेकिन उनके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। उनकी हिम्मत इसलिए बढ़ती है, क्योंकि वो पहले भी कई बार हमारे देश की बेटियों को अपमानित कर चुके हैं। तब भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई।

शिवराज की पत्नी के अपमान पर मंत्री पद से हटाया था

रीना बोरासी ने कहा- 2013 में उन्होंने शिवराज जी पत्नी का अपमान किया था। चूंकि वे बीजेपी लीडर की धर्मपत्नी थी तब उनको मंत्रिपद से बर्खास्त से कर दिया था। मैं मोहन यादव से पूछना चाहती हूं कि सम्मान सिर्फ आपकी महिलाओं का है बाकी महिलाओं हमारे देश की बेटी और लाड़ली बहना का सम्मान नहीं हैं। आपके किसी नेता की पत्नी के लिए बोलेंगे तो आप बर्खास्त कर देंगे और जब देश की बेटी के लिए बोलेंगे या लाड़ली बहना के लिए बोले तो आपने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। अगर उन्हें मंत्रिपद से बर्खास्त नहीं करते, या इस्तीफा नहीं दिलवाते तो हमारा विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। जब तक वो इस्तीफा नहीं देते या सार्वजनिक तौर पर माफी नहीं मांगते तब तक महिला कांग्रेस का विरोध जारी रहेगा।

पश्चिमी सभ्यता के खिलाफ मुस्लिम त्योहार कमेटी ने किया प्रदर्शन

कहा- अश्लील आयोजनों से युवाओं की सोच प्रभावित, देशभर में चलेगा अभियान

भोपाल (नप्र)। भारतीय संस्कृति और पारंपरिक मूल्यों की रक्षा के उद्देश्य से ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी ने राजधानी भोपाल से 'पश्चिमी सभ्यता के खिलाफ जन-जागरूकता अभियान' की शुरुआत की। अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में कमेटी के संरक्षक शमशुल हसन ने पश्चिमी प्रभावों पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि यह मुहिम केवल मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरे देश में निरंतर जारी रहेगी।

शमशुल हसन बल्ली ने कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी उन सभी गतिविधियों का विरोध करती आई है जो देश, संस्कृति और समाज के नैतिक मूल्यों के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि आज पश्चिमी सभ्यता के नाम पर युवाओं के सामने जिस तरह की नग्नता और अश्लीलता परोसी जा रही है, उसका सीधा असर हमारी नई पीढ़ी, बहनों और बेटियों पर पड़ रहा है। इसे रोकना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भोपाल से शुरू किया गया यह अभियान अब देशभर में कमेटी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के माध्यम से चलाया जाएगा। जहां-जहां इस तरह के आयोजनों में अश्लीलता या सामाजिक मर्यादाओं का उल्लंघन होगा, वहां कमेटी निगरानी रखेगी और विरोध दर्ज कराएगी।

कार्यक्रम में मौजूद वक्ताओं ने कहा कि इस मुहिम का उद्देश्य किसी विशेष समुदाय या त्योहार का विरोध करना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि सभी उत्सव भारतीय परंपराओं और सांस्कृतिक मूल्यों के अनुरूप मनाए जाएं। उन्होंने कहा कि भारतीय सभ्यता में उत्सव आनंद और संस्कार का प्रतीक रहे हैं, न कि नग्नता और भड़काऊ प्रस्तुतियों का।

इस अवसर पर कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष तनवीर कुरेशी, प्रदेश मीडिया प्रभारी आरिफ खान सहित बड़ी संख्या में समिति के सदस्य और आम नागरिक मौजूद रहे। सभी ने एक स्वर में भारतीय संस्कृति की रक्षा और युवाओं को सही दिशा देने के लिए इस अभियान को निरंतर जारी रखने का संकल्प लिया।

पीएम मोदी एवं मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कृषि के क्षेत्र में प्रदेश लगातार कर रहा प्रगति : कंषाना

भोपाल (नप्र)। किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री एदल कंषाना सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र दी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में कृषि के क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रहा है। हमारी सरकार विकास और सेवा के दो वर्ष पूर्ण कर मुख्यमंत्री डॉ. यादव का समृद्ध मध्यप्रदेश का सपना पूर्ण कर रही है। यह बात मंत्री श्री कंषाना ने जनसंपर्क संचालनालय के सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश आज देश के अग्रणी कृषि राज्यों में शामिल है।

सोयाबीन एवं मक्का के उत्पादन में प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है तथा गेहूं, उड़द, मसूर, चना, सरसों, कुल तिलहन, कुल दलहन, कुल अनाज और मोटा अनाज में मध्य प्रदेश का देश में द्वितीय स्थान है। यह हमारे किसानों की मेहनत और सरकार की किसान-हितैषी नीतियों का प्रतिफल है। प्रदेश के अन्नदाताओं की कड़ी मेहनत से ही यह उपलब्धियां हासिल करने में हम सफल हुये है।

कृषि मंत्री श्री कंषाना ने कहा कि वर्ष 2002-2003 में सिंचाई का क्षेत्रफल लगभग साढ़े सात लाख हेक्टेयर था जो कि 2024-25 में 55 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सिंचाई की जा रही है। आगामी 3 वर्षों में सिंचाई का रकबा बढ़ाकर65 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य है। जैविक एवं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है।

जनजातीय अंचलों में श्रीअन्न को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गई है, जिससे कोदो-कुटकी जैसी पारंपरिक फसलों का उत्पादन, विपणन की व्यवस्था की जा रही है, ताकि किसानों की आय में वृद्धि हो सके। किसानों की सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत करोड़ों रुपये की सहायता राशि सीधे किसानों तक पहुँची है। प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को राहत राशि का त्वरित वितरण किया गया है।

कृषि मंत्री श्री कंषाना ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के 8 जिले अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, सीधी, अलीराजपुर, निमाड़ी, टीकमगढ़ एवं डिण्डोरी को शामिल किया गया है।

इन आकांक्षी जिलों में कृषि उत्पादन, ग्रामीण समृद्धि और योजनाओं के समन्वय पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वर्ष 2024-25 में सोयाबीन, चना, मसूर, धान एवं गेहूं की खरीदी के माध्यम से किसानों को हजारों करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।

प्रदेश में प्राकृतिक खेती, तिलहन-दलहन आत्मनिर्भरता मिशन, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, ई-नाम, कृषि अद्योसंरचना निधि और कृषि निर्यात जैसे क्षेत्रों में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। कृषि को लाभकारी व्यवसाय बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं। हमारा संकल्प है कि किसान की आय बढ़े, खेती टिकाऊ बने और मध्य प्रदेश कृषि में देश का नेतृत्व करें।

संपादकीय

ईडी की कार्यप्रणाली पर सवाल

नेशनल हेराल्ड केस में जिस तरह दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी द्वारा दायर चार्जशीट का संज्ञान लेने इंकार किया है, उससे ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) की कार्यप्रणाली पर ही सवाल उठने लगे हैं। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में ईडी ने कानूनी प्रक्रिया का ठीक से पालन नहीं किया। किसी एक व्यक्ति की शिकायत पर ईडी जांच नहीं कर सकती। इस साल अप्रैल में दायर अपनी चार्जशीट में ईडी ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत अन्य लोगों ने पैसों का घोटाला किया था। ईडी की चार्जशीट को प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट भी कहा जाता है। चार्जशीट दायर करने के बाद कोर्ट को उसका संज्ञान लेना होता है। फिर मामला आगे बढ़ता है। इस आदेश को कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ी जीत बताया। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ये फ़ैसला एजेंसी के दुरुपयोग का प्रमाण है। दूसरी ओर, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि इस फ़ैसले से नेशनल हेराल्ड मामले में 'क्लीन चिट' नहीं मिली है। एक टेक्निकल आधार पर ट्रायल कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया, लेकिन मामला अब भी चल रहा है। ईडी चाहे तो इस फ़ैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दे सकती है। हालांकि जानकार इसे बड़ा फैसला मान रहे हैं। गौरतलब है कि 2013 में तत्कालीन भाजपा सांसद डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी ने अदालत में एक शिकायत दर्ज कराई। इसमें उन्होंने कहा कि सोनिया और राहुल गांधी समेत कई लोगों ने 'एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल)' की क़रीब 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति को केवल 50 लाख रुपए में 'यंग इंडियन' नाम की एक कंपनी को दे दिया। एजेएल कंपनी नेशनल हेराल्ड अख़बार को छापती है। इसकी शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने की थी। सुब्रमण्यम स्वामी ने इसमें 'धोखाधड़ी' और 'आपराधिक षड्यंत्र', समेत अन्य आरोप लगाए। उनकी याचिका पर कोर्ट ने 2014 में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, और अन्य लोगों को पेश होने का आदेश दिया। इसी दौरान 2021 में ईडी ने इस आधार पर एक शिकायत दर्ज की। ईडी की शिकायत को 'एनफ़ोर्समेंट केस इनफ़ॉर्मेशन रिपोर्ट' कहते हैं। इस शिकायत की जाँच करने के बाद ईडी ने इस साल अपनी चार्जशीट दायर की। इसमें उन्होंने राहुल गांधी और सोनिया गांधी, समेत अन्य लोगों पर पैसों के घोटाले का आरोप लगाया। इस चार्जशीट में कुल सात अभियुक्त थे, जिसमें यंग इंडियन कंपनी के साथ-साथ उनके निदेशक सुमन दुबे और सैम पित्रोदा भी शामिल थे। आमतौर पर किसी भी अपराध में पहले पुलिस एफआईआर दर्ज कर उसकी तहकीकात कर कोर्ट में चार्जशीट दायर करती है। उसका संज्ञान लेने के बाद कोर्ट तय करती है कि किन आधारों पर मुकदमा चलना चाहिए। अगर पैसों की हेराफेरी हुई है तो ईडी उसकी जांच करती है। नेशनल हेराल्ड मामले में आरोपियों का कहना था कि चूंकि इस मामले में पुलिस में कोई शिकायत या एफ़आईआर दर्ज नहीं की थी, इसलिए ईडी इस मामले में आगे जांच नहीं कर सकती है। कोर्ट ने अभियुक्त के तर्कों से सहमति जताते हुए कहा कि ईडी पैसों के घोटाले के लिए तभी जाँच कर सकती है, जब कोई एफ़आईआर के तहत जांच से वह अपराध उजागर हो, जिससे पैसे आए हों। कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट का संज्ञान लेने से मना कर दिया। कोर्ट ने इस बात पर फ़ैसला नहीं दिया है कि नेशनल हेराल्ड मामले में पैसों का घोटाला हुआ है या नहीं। विशेषज्ञों के अनुसार जब कोर्ट चार्जशीट का संज्ञान लेने से मना कर देती है, तो मामला वहीं ख़त्म हो जाता है। बहरहाल यह ईडी और मोदी सरकार के लिए भी झटका है।

एसआईआर अपडेट से बदल सकता है यूपी का चुनावी नक्शा

नजरिया

अजय कुमार
लेखक लखनऊ निवासी वरिष्ठ पत्रकार हैं।

चुनाव आयोग इसे नियमित और जरूरी कवायद बता रहा है, जबकि राजनीतिक दल इसे अपने-अपने चश्मे से देख रहे हैं. एक तरफ बीजेपी फर्जी, डुप्लीकेट और घुसपैठियों के नाम हटाने की बात कर रही है, दूसरी तरफ विपक्ष को आशंका है कि इस प्रक्रिया की आड़ में गरीब, अल्पसंख्यक और प्रवासी तबके के वोट काटे जाएंगे. एसआईआर की शुरुआत 1 नवंबर 2025 से हुई. जनवरी 2025 की मतदाता सूची के मुताबिक उत्तर प्रदेश में कुल 15.44 करोड़ मतदाता दर्ज थे. आयोग का उद्देश्य साफ है मृत मतदाताओं, स्थानांतरित हो चुके लोगों, दोहरी प्रविष्टियों और फर्जी नामों को हटाना, साथ ही नए योग्य मतदाताओं को जोड़ना. इसके लिए बूथ लेवल ऑफिसर के जरिए घर-घर सत्यापन कराया गया. यह प्रक्रिया पहले भी होती रही है, लेकिन इस बार विवाद इसलिए गहरा गया क्योंकि सत्ताधारी दल के शीर्ष नेताओं के बयान सियासी आग में घी डालने लगे.

उत्तर प्रदेश की राजनीति इन दिनों मतदाता सूची के एक तकनीकी से दिखने वाले, लेकिन असर में बेहद सियासी मुद्दे के इर्द-गिर्द घूम रही है. स्पेशल इंटेंसिव रिविजन यानी एसआईआर को लेकर ऐसा घमासान मचा है कि यह प्रक्रिया 2027 के विधानसभा चुनाव की बुनियाद बनती नजर आ रही है. चुनाव आयोग इसे नियमित और जरूरी कवायद बता रहा है, जबकि राजनीतिक दल इसे अपने-अपने चश्मे से देख रहे हैं. एक तरफ बीजेपी फर्जी, डुप्लीकेट और घुसपैठियों के नाम हटाने की बात कर रही है, दूसरी तरफ विपक्ष को आशंका है कि इस प्रक्रिया की आड़ में गरीब, अल्पसंख्यक और प्रवासी तबके के वोट काटे जाएंगे. एसआईआर की शुरुआत 1 नवंबर 2025 से हुई. जनवरी 2025 की मतदाता सूची के मुताबिक उत्तर प्रदेश में कुल 15.44 करोड़ मतदाता दर्ज थे. आयोग का उद्देश्य साफ है मृत मतदाताओं, स्थानांतरित हो चुके लोगों, दोहरी प्रविष्टियों और फर्जी नामों को हटाना, साथ ही नए योग्य मतदाताओं को जोड़ना. इसके लिए बूथ लेवल ऑफिसर के जरिए घर-घर सत्यापन कराया गया. यह प्रक्रिया पहले भी होती रही है, लेकिन इस बार विवाद इसलिए गहरा गया क्योंकि सत्ताधारी दल के शीर्ष नेताओं के बयान सियासी आग में घी डालने लगे.

14 दिसंबर 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की एक बैठक में कहा कि एसआईआर के बाद प्रदेश की मतदाता सूची से करीब चार करोड़ नाम हट सकते हैं. उन्होंने यह भी जोड़ा कि इनमें से 85 से 90 फीसदी नाम बीजेपी समर्थकों के हैं. यह बयान आते ही सियासी हलकों में खलबली मच गई. सवाल उठने लगे कि अगर वास्तव में चार करोड़ नाम हटते हैं तो यह प्रदेश की राजनीति का चेहरा बदल सकता है. योगी के मुताबिक, अब तक करीब 12 करोड़ नाम ही रिकॉर्ड हो पाए हैं, जबकि आबादी के अनुपात में यह संख्या ज्यादा होनी चाहिए. उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे बूथ स्तर पर सक्रिय होकर छूटे हुए नामों को जोड़वाएं.योगी के बयान के कुछ ही दिन बाद, 17 दिसंबर को पूर्व बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने एक अलग ही दावा कर दिया. उन्होंने कहा कि कन्नौज लोकसभा क्षेत्र की तीन विधानसभा सीटों में ही करीब तीन लाख नाम कट सकते हैं और ये ज्यादातर समाजवादी पार्टी के वोटर हैं. यह बयान योगी के दावे से उलट दिशा में जाता दिखा. एक तरफ मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बीजेपी समर्थकों के नाम ज्यादा कट रहे हैं, दूसरी तरफ पार्टी के ही एक वरिष्ठ नेता दावा कर रहे हैं कि नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा. यहीं से एसआईआर पर सवाल और गहरे हो गए.

विपक्ष ने इन बयानों को हाथों हाथ लपक लिया. समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि अगर चार करोड़ नामों में 85 फीसदी बीजेपी के हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि बीजेपी के साढ़े तीन करोड़ वोटर फर्जी थे. उन्होंने चुनाव आयोग से पूरी प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच की मांग की. कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने भी आरोप लगाया कि एसआईआर के नाम पर वोट काटने की साजिश रची जा रही है, खासकर उन इलाकों में जहां गरीब, मजदूर और अल्पसंख्यक आबादी ज्यादा है.असल में, अभी तक चुनाव आयोग ने कोई आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया है. ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जनवरी 2026 में आएगी और फाइनल सूची फरवरी में प्रकाशित होगी. यानी फिलहाल जो भी दावे किए जा रहे हैं, वे प्राथमिक फीडबैक, कार्यकर्ताओं की रिपोर्ट और अनुमान पर आधारित हैं. यही वजह है कि आंकड़ों से ज्यादा बयानबाजी सुर्खियों में है.योगी आदित्यनाथ के चार करोड़ वाले दावे के पीछे जो गणित बताया जा रहा है, वह भी चर्चा में है. यूपी की आबादी करीब 25 करोड़ मानी जाती है. अगर इसमें 65 फीसदी वयस्क मतदाता मानें, तो आंकड़ा करीब 16 करोड़ के आसपास बैठता है. इसमें हर साल 18 साल पूरे करने वाले नए वोटरों को जोड़ना भी शामिल है. ऐसे में 12 करोड़ नाम रिकॉर्ड होने की बात सुनकर चार करोड़ का अंतर निकालना आसान है. लेकिन यह अंतर वास्तव में नाम कटने का है या अब तक सत्यापन में न आ पाने का, यह साफ नहीं है.

बीजेपी के भीतर भी यह माना जा रहा है कि शहरी इलाकों में बड़ी संख्या में लोग काम के सिलसिले में दूसरे शहरों में रहते हैं, लेकिन गांव का वोट बनाए रखते हैं. सत्यापन के समय ऐसे कई नाम छूट जाते हैं. योगी का जोर इस बात पर था कि पार्टी कार्यकर्ता समय रहते ऐसे मतदाताओं का फॉर्म भरवाएं. उनके भाषण में बांग्लादेशी घुसपैठियों और उम्र में गड़बड़ी वाले उदाहरण भी आए, जिसने पूरे मुद्दे को राष्ट्रीय सुरक्षा और पहचान की राजनीति से जोड़ दिया. दूसरी ओर, सुब्रत पाठक का बयान कन्नौज जैसे समाजवादी पार्टी के मजबूत गढ़ से जुड़ा है. 2019 में यहां से सांसद रहे पाठक 2024 में अखिलेश यादव से चुनाव हार चुके हैं. ऐसे में उनके बयान को स्थानीय सियासत और 2027 की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है. उनका दावा है कि फर्जी और डुप्लीकेट नामों का सबसे ज्यादा फायदा समाजवादी पार्टी को मिला है और एसआईआर के बाद उसकी असलियत सामने आ जाएगी. हालांकि, इस दावे के समर्थन में भी कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है.

चुनाव आयोग ने बार-बार कहा है कि एसआईआर पूरी तरह पारदर्शी प्रक्रिया है और किसी भी नाम को हटाने से पहले नोटिस और अपील का मौका दिया जाता है. आयोग का कहना है कि अंतिम सूची आने से पहले किसी भी तरह का निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी. इसके बावजूद राजनीतिक बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही.अगर दूसरे राज्यों के अनुभव देखें तो तस्वीर थोड़ी साफ होती है. बिहार और पश्चिम बंगाल में हुए एसआईआर में बड़ी संख्या में युवा मतदाताओं के नाम जुड़े हैं, जबकि मृत, डुप्लीकेट और लंबे समय से बाहर रह रहे लोगों के नाम कटे हैं. वहां किसी एक पार्टी को सीधा फायदा या नुकसान होने की बात साफ तौर पर सामने नहीं आई. यूपी में भी यही पैटर्न दोहराया जा सकता है, लेकिन यहां का पैमाना और सियासी दांव कहीं बड़े हैं. सवाल आखिर में यही है कि मतदाताओं की संख्या घटने या बढ़ने से फायदा किसे होगा. इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है. यह इस बात पर निर्भर करेगा कि किन इलाकों में, किस सामाजिक वर्ग के और किस उम्र के मतदाताओं के नाम सूची से बाहर होते हैं या जुड़ते हैं. फिलहाल इतना तय है कि एसआईआर ने 2027 के चुनाव से पहले राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है. जब तक जनवरी-फरवरी 2026 में आधिकारिक आंकड़े सामने नहीं आते, तब तक योगी हों या अखिलेश, हर बयान सियासत का हिस्सा बना रहेगा और वोटर लिस्ट राजनीति का सबसे बड़ा हथियार बनी रहेगी.

परमाणु ऊर्जा शांति विधेयक-2025

जरूरी है परमाणु जवाबदेही बाधाओं से मुक्ति

प्रमोद भार्गव
लेखक पत्रकार हैं।

आखिरकार नरेंद्र मोदी सरकार ने विपक्ष के तमाम विरोध और हंगामे के बावजूद 'शांति विधेयक-2025' अर्थात् 'भारत परिवर्तन के लिए नाभिकीय ऊर्जा का सतत दोहन तथा उन्नयन विधेयक-2025' लोकसभा से पारित करा लिया। इस विधेयक का उद्देश्य परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 और परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम 2010 को निरस्त करना है। दरअसल भारत ने 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा बनाने का लक्ष्य रखा है। इसे हासिल करने की दृष्टि से ऊर्जा विशेषज्ञों का मानना है कि इस बड़े लक्ष्य को प्राप्ती के लिए निजी कंपनियों का सहयोग जरूरी है। अकेली सरकारी संस्थाओं के बूते इस मकसद को पूरा करना मुमकिन नहीं है। अतएव इस नए विधेयक के आने से परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने की उम्मीद की जा रही है। यह विधेयक परमाणु ऊर्जा के लिए एक सुरक्षित कानूनी ढांचा तैयार करेगा। फलस्वरूप निजी कंपनियां इस क्षेत्र में काम कर सकेंगी। इस क्षेत्र में अभी तक परमाणु ऊर्जा विभाग का ही कब्जा है। इस विधेयक के बाद अतिरिक्त बिजली उत्पादन, ग्रिड एकीकरण और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से विकास होगा।

नागरिक दायित्व अधिनियम (सीएलएनडीए) 2010 में दो महत्वपूर्ण संशोधन सरकार कर सकती है। इन दो संशोधनों को बड़े सुधारों के रूप में देखा जा रहा है। इस संशोधन के तहत परमाणु संयंत्रों को उपकरण सप्लाई करने वाली कंपनियों की जिम्मेदारी सीमित की जा सकती है। मसलन यदि कोई दुर्घटना होती है तो उनकी जिम्मेदारी अनुबंध की मूल राशि और एक निर्धारित समय तक ही सीमित रहेगी। इस परिप्रेक्ष्य में बतौर उदाहरण विदेशी कंपनी जैसे जीई-हिताची वेस्टिंग हाउस को इस कानून के कारण निवेश में हिचक होती रही है। दूसरा संशोधन परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 में प्रस्तावित है। यह कानून फिलहाल केवल सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों को ही परमाणु संयंत्र चलाने की अनुमति देता है। इसे संशोधित किया जाता है तो निजी कंपनियों को भी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के संचालन की अनुमति मिल जाएगी। इस परिवर्तन से विदेशी कंपनियों के लिए भविष्य के परमाणु प्रोजेक्ट में अंशिक हिस्सेदारी का द्वार खुल जाएगा। साफ है, ये उपाय हो जाते हैं तो परमाणु उत्पादन बढ़ने की संभावनाएं तो बढ़ जाएंगी, लेकिन स्वच्छ ऊर्जा और परमाणु दुर्घटना होने पर कंपनियों को नागरिक जवाबदेही से मुक्ति मिल जाएगी। याद रहे मनमोहन सिंह सरकार के प्रधानमंत्री रहते हुए भारत-अमेरिका के बीच हुए परमाणु समझौते के बाद जो राजनीतिक तूफान उठा था, उसके चलते संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन-1 सरकार गिरते-गिरते बची थी।

दरअसल सरकार परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को बाधा मुक्त इसलिए करना चाहती है जिससे 2047 तक सौ गीगावाट परमाणु ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य हासिल कर लिया जाए। इसी लक्ष्य पूर्ति के लिए सरकार परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी भागीदारी बढ़ाना चाहती है। इसीलिए 2024-25 के आम बजट में लघु परमाणु संयंत्रों के लिए सरकार ने बड़े बजट का प्रावधान किया था। इस क्षेत्र में नया प्रयोग करते हुए पहली बार निजी कंपनियों को लघु परमाणु संयंत्र समूचे देश में स्थापित करने का अवसर दिया जाएगा। कालांतर में विदेशी कंपनियों को भी परमाणु संयंत्र लगाने की अनुमति दी जा सकेगी। साथ ही मॉड्यूलर (प्रतिरूपक) रिएक्टर के आधुनिकीकरण के लिए शोध और विकास पर भी धनराशि खर्च की जाएगी। जिससे परमाणु ऊर्जा में नई प्रौद्योगिकी का विकास हो, इसे पीपीपी मॉडल पर क्रियान्वित किया जाएगा। इसका उद्देश्य देश में स्वच्छ एवं वैकल्पिक बिजली को बढ़ावा देना है। फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका यात्रा पर गए थे, तब भारत में छोटे परमाणु संयंत्र लगाने और भारत में ही उत्पादन करने का समझौता हुआ था। एआई के दौर में ऊर्जा की खपत असाधारण रूप से बढ़ने की उम्मीद है। यह एक कंप्यूटर की भाषा का कृत्रिम बुद्धि से जुड़ा मॉडल है। भाषा मॉडल ऐसे मशीन लर्निंग मॉडल हैं, जो मानव भाषा के पाठ को समझ सकते है और सृजित भी कर सकते हैं। ये मॉडल भाषा के बड़े डेटा भंडार का विश्लेषण करने पर भी सक्षम होते हैं। सुपर और क्वांटम कंप्यूटर में इसी एआई की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए परमाणु ऊर्जा की जरूरत लघु परमाणु संयंत्रों से ही संभव हैं। स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन में इसे क्रांतिकारी पहल माना जा रहा है।

विकसित भारत के लिए ऊर्जा की उपलब्धता एक बड़ी जरूरत है। इसलिए सरकार सिर्फ पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भर नहीं रहना चाहती है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से हमारी सेना ने पाकिस्तान के आतंकी और गैर-सैन्य ठिकानों को ध्वस्त किया था, उन आयुधों के निर्माण और संचालन के लिए भी परमाणु ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। इस परिप्रेक्ष्य में सौर और पवन ऊर्जा पर सरकार पहले ही काफी कुछ कर चुकी है। अतएव अब फोकस परमाणु ऊर्जा पर केंद्रित है। क्योंकि इसमें संभावनाएं अधिक हैं। आम बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने ऊर्जा सुरक्षा को सरकार की नौ प्राथमिकताओं में गिनाया था। ऊर्जा बदलाव के संबंध में एक नीतिगत दस्तावेज तैयार करने की बात भी कही गई है। इससे यह तय होगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में किस तरह से पारंपरिक ऊर्जा की जगह धीरे-धीरे अपारंपरिक ऊर्जा के स्रोत का महत्व बढ़ रहा है। यह दस्तावेज ऊर्जा क्षेत्र में रोजगार, विकास और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों का भी समाधान खोजेगा। अतएव इसी परिप्रेक्ष्य में निकेल, कोबाल्ट, तांबा और लिथियम जैसी धातुओं के उत्पादों के आयात पर शुल्क घटाया है। इन उत्पादों का प्रयोग परमाणु और सौर ऊर्जा के साथ दूसरे ऊर्जा उत्सर्जन उपायों में भी होता है। आयात सस्ता होने से इनका निर्माण भारत में करने में आसानी होगी। यही नहीं परमाणु ऊर्जा, नवीनीकरण ऊर्जा और अंतरिक्ष एवं रक्षा क्षेत्रों में इस्तेमाल होने वाली 25 धातुओं पर सीमा शुल्क को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। यानी छोटे परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के रास्ते साफ किए जा रहे हैं।

हालांकि परमाणु ऊर्जा से उत्पन्न खतरों की आशंकाएं भी एकदम बेबुनियाद नहीं हैं। इसलिए परमाणु संयंत्रों की सुरक्षा भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। रूस के चेर्नोबिल और जापान के फुकुशिमा परमाणु संयंत्र में हादसे के बाद इस तरह की चिंताएं जरूरी हैं। क्योंकि वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद प्राकृतिक आपदाओं के सामने हम बौने हैं। जापान में महज दस सेकेंड के लिए आई सुनामी नामक विराट आपदा ने फुकुशिमा की वैज्ञानिक उपलब्धियों को चकनाचूर कर दिया था। सृष्टि को संजीवनी देने वाले तत्व हवा, पानी और अग्नि जब न्यूनतम मर्यादाओं की सीमा लांघकर भीषण विराटता रचते हैं तो दसों दिशाओं में सिर्फ और सिर्फ विनाशलीला का मंजर दिखाई देता है। इसलिए जरुरी है कि परमाणु रिएक्टर प्रदायक कंपनियों को कड़ी शर्तों के तहत मुआवजे के प्रावधान निर्धारित हों या फिर बीमा कंपनियों को दुर्घटना की स्थिति में क्षतिपूर्ति से जोड़ा जाए।

परमाणु बिजली संयंत्रों में ग्रेफाइट मॉडरेट के रुप में प्रयोग होता है। जिसमें पानी की बहुत थोड़ी मात्रा विलय करने से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के विखण्डन के समय बहुत अधिक तापमान के साथ उर्जा निकलती है। इस उर्जा का दबाव टर्बाइन को तीव्रतम गति से घुमाने का काम करता है। नतीजतन बिजली उत्पन्न होती है। रिएक्टरों के इस उच्चतम तापमान को एक सेंटीग्रेट तक काबू में रखने के लिए रिएक्टरों पर ठंडे पानी की निरंतर प्रबल धाराएं छोड़ी जाती हैं। हालांकि प्राकृतिक अथवा अन्य आपदा की स्थिति में ये परमाणु संयंत्र अचूक कंप्यूटर प्रणाली से संचालित व नियंत्रित होने के कारण खुद-ब-खुद बंद हो जाते हैं। लेकिन इस अवस्था में विरोधाभासी स्थिति यह होती है कि जल से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का नाभिकीय विखण्डन तो थम जाता है, किंतु रासायनिक प्रक्रियाएं और भौतिक दबाव एकाएक नहीं थमते। गोया, जलधारा का प्रवाह बंद होते ही रिएक्टरों का तापमान 5000 डिग्री सेंटीग्रेट से बढ़कर 10000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पंहुच जाता है। यह तापमान जीव-जंतुओं को तो क्या स्टील जैसी ठोस धातु को भी पल भर में गला देता है। इस लिहाज से इन संयंत्रों के संभावित खतरों को एकाएक नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

विदेशी चमक बनाम स्वदेश की शक्ति

भारतीय युवा

डॉ. मनमोहन प्रकाश
लेखक प्रोफेसर हैं।

आज की भारतीय युवा पीढ़ी इतिहास के निर्णायक संक्रमण काल में खड़ी है। एक ओर विदेशी जीवन की झिलमिलाती चमक, उच्च वेतन, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की प्रतिष्ठा तथा तथाकथित 'ग्लोबल लाइफस्टाइल' उसे लुभा रही है; दूसरी ओर स्वदेश की माटी की खुशबू, पारिवारिक प्यार, समाज का अपनापन तथा राष्ट्र-दायित्व की मौन पुकार जड़ों से जुड़े रहने का आह्वान कर रही है। यह द्वंद्व केवल रोजगार या करियर का नहीं, अपितु आत्म-पहचान, सांस्कृतिक स्वाभिमान तथा राष्ट्र-भविष्य से जुड़ा गहन विमर्श है। युवाओं को निर्णय लेते समय यह ध्यान रखना होगा कि भारत अब अवसर-विहीन देश नहीं; विश्व की सबसे तेज अर्थव्यवस्थाओं में शुमार है तथा 'विकसित भारत' के लक्ष्य हेतु संकल्पबद्ध है।आरबीआई आंकड़ों के अनुसार, बीते वर्षों में लाखों युवा पेशेवर विदेश गये, किंतु 'रिवर्स ब्रेन ड्रेन' की प्रवृत्ति भी उभर रही है। जब अपने ही देश में अवसरों का विस्तार हो रहा है, तब विदेश-आकर्षण का रहस्य क्या है?

आधुनिक भारत तकनीक, ऑटोमोबाइल, वस्त्र, फार्मा, कृषि-प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी, हस्तशिल्प, अंतरिक्ष तथा रक्षा जैसे क्षेत्रों में वैश्विक केंद्र बन रहा है। टाटा, रिलायंस, इंफोसिस, टीसीएस, महिंद्रा जैसी कंपनियाँ तथा नवरत्न संस्थान बौद्धिक क्षमता, नवाचार और आत्मनिर्भरता के प्रतीक बने हुए हैं। इसरो, डीआरडीओ, बीएआरसी , एचएएल, सीएसआईआर, आईसीएआर, आईसीएमआर, आईआईटी, आईआईएम, आईआईएससी तथा एम्स जैसे संस्थान अंतरिक्ष, रक्षा, चिकित्सा तथा विज्ञान में राष्ट्र-निर्माण को सशक्त कर रहे हैं। चंद्रयान-तीन की सफलता, एक साथ कई उपग्रह प्रक्षेपण की क्षमता, रक्षा में स्वदेशीकरण, डिजिटल इंडिया का समावेशन, 1.2 लाख स्टार्टअप्स (100+ यूनिकॉर्न सहित), मेक इन इंडिया तथा नवीकरणीय ऊर्जा में प्रगति प्रमाणित करते हैं कि भारत अब अवसरों का निर्यातक बन चुका है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 ने शिक्षा-शोध-नवाचार को नई दिशा दी है। नैस्कॉम रिपोर्ट्स के अनुसार, टियर-दो, तीन शहरों में लगभग चालीस प्रतिशत नई नौकरियाँ सृजित हो रही हैं तथा सरकारी योजनाएँ स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण और ऋण प्रदान कर रही हैं।फिर भी अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन तथा ऑस्ट्रेलिया आदि की ओर युवाओं का रुझान तथा माता पिता की इच्छा बनी हुई है। शायद बेहतर वेतन, जीवन-शैली तथा वैश्विक अनुभव के कारण। सोशल मीडिया, ओटीटी तथा पॉप-संस्कृति ने योजनाबद्ध तरीके से विदेश विशेष कर पश्चिम को सफलता का पर्याय गढ़ा है।किंतु भारतीय युवाओं को यह भी जानना होगा कि विदेशों में महँगाई, एकाकीपन, सांस्कृतिक दूरी, नस्लीय भेदभाव तथा मानसिक तनाव जैसे कठोर यथार्थ भी छिपे हैं। भारतीय चिंतन में जीवन ऋण-चुकाने से जुड़ा है,वो भी माता-पिता, समाज तथा मातृभूमि का। साथ ही सर्वश्रेष्ठ संस्थानों से निकली प्रतिभा का स्थायी विदेश-प्रवास कहीं न कहीं राष्ट्र-विकास को क्षति पहुँचाता है। मेरे विचार में विदेश जाना ज्ञान-अर्जन हेतु उचित है, किंतु भावनात्मक-बौद्धिक कटाव अनुचित है। 'ब्रेन गेन' तभी संभव जब अनुभव स्वदेश के उत्थान में लगे। अतः समाधान न विदेश-रोक में है, न अंध स्वदेश-उन्माद में, आवश्यकता है संतुलित दृष्टि की। युवा वैश्विक पंख अवश्य फैलाएँ, किंतु अपनी जड़ों से जुड़े रहें। नीति-निर्माताओं का भी दायित्व है कि वे युवाओं के लिए बेहतर शिक्षा, रोजगार तथा व्यापार के समान अवसर सभी राज्यों में पैदा करें । समाज-परिवार की भी जिम्मेदारी है कि वे युवाओं में देश प्रेम और आत्मविश्वास जगाएँ,भारत में रहकर वैश्विक सफलता अर्जित करें जो आज की परिस्थितियों में संभव है। युवाओं को समझना होगा कि विदेशी चमक क्षणिक मृगतृष्णा है, स्वदेश की शक्ति शाश्वत। युवा यदि अपनी प्रतिभा को देश को समर्पित कर दें, तो उनका भविष्य सुदृढ़ तो होगा ही, भारत की वैश्विक पहचान दीप्तिमान भी होगी।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
वरिष्ठ संपादक
पंकज शुक्ला
प्रबंध संपादक
अरुण पटेल
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923,
Ph. No. 0755-2422692, 4059111
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

व्यंग्य

हिन्दी की खिचड़ी में अंग्रेजी दाल

सुधीर देशपांडे
लेखक व्यंग्यकार हैं।

कुछ अखबारों ने अपनी भाषा खिचड़ी बना दी है। जिसमें दाल यानी अंग्रेजी ज्यादा है और चावल कम। अखबार लिखा तो देवनागरी में जाता है, पर मजा अंग्रेजी पढ़ने का दे जाता है। कुछ समझ आता है तो कुछ ऊपर से जाता है। लगता है कि अक्षर जोड़ने वाला देशी शराब पीने के बाद अखबार के लिए अक्षर जोड़ रहा है। कई बार ऐसा भी लगता है, जैसे नई नई अंग्रेजी सीखने वाला, जहाँ नहीं, वहाँ भी अंग्रेजी का तड़का वैसे ही लगा रहा है, जैसे लौकी की साग में बहते तेल में तेज मिर्च का तड़का लगा दिया हो ताकि खाते हुए सब्जी की दूसरी कमियों पर ध्यान ही न जाए।

कई बार सुबह घूमने जाने वाले मित्र आपको कहते मिलेंगे कि 'जब मैं सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर घूमने गया था, तब मेरे साथ एक दर्दनाक वाकया हुआ।' जो इस भाषा के साथ हुए दर्दनाक वाकये से गुजर रहें हों उनके दर्द का अनुभव वही जानता है, जिसने उसे भोगा हो। जाके पैर न फटे बीवाई, वो क्या जाने पीर पराई। एक मित्र यह कहता भी दिखाई देता है कि आज दोपहर का लंच हमारे साथ कीजिए। अब मैं शाम के लंच के निमंत्रण की प्रतीक्षा में हूँ।

अब तो हिन्दी के कई लेखकों ने भी अपनी भाषा में अंग्रेजी मसालों का प्रयोग आरंभ कर दिया है। वस्तुतः यह सब प्रगतिशीलता का द्योतक है। यह खिचड़ी वे कॉन्वेन्टी छात्रों के लिये पाते हैं। जैसे प्रगतिशील लोग, जींस पर कुर्ता पहन कर क्रांति का अलख फूँकते मिलते है। भाषा की शुचिता तो पुरातनपंथियों के ढकोसले हैं। आखिर आज के जमाने में शुद्ध क्या है? न घी, न दूध, न सांग, न चिंतन, न ही मनन। बच्चों से शुद्ध भाषा का आग्रह करो तो उनका जवाब यही रहता है। आपने शुद्ध घी खाया है, तो दिमाग पर जोर दे देकर नये नये पुराने शब्द खोज खोजकर लाते हो। हमें कहाँ कुछ शुद्ध मिला है, जो शुद्ध भाषा की बात कर रहे हैं? अंग्रेजी भाषा का प्रभाव ही ऐसा है कि हिन्दी भी ठीक से न जानने वाली माँ, अपने बच्चे को अंग्रेजी माध्यम की स्कूल में जिसमें मीडियम की अंग्रेजी वर्तनी भी ग़लत लिखी होती है, में भर्ती करने को लालायित रहती है। सपने देखने पर रोक नहीं है, पर सपने ढो भी सकते हैं या नहीं इसका इल्म तो हो। अब ऐसे बच्चे जो न हिन्दी के रहे न अंग्रेजी के, उनके लिए ऐसे अखबार वकालत करते हैं।

शिक्षा की प्रयोगशाला में भी कुछ साल पहले द्विभाषिक पहुँच का प्रयोग किया गया था। वैसे भी हमारे विद्यालय बड़ी प्रयोगशालाएँ हैं, जहाँ सीखने के और सिखाने के तमाम प्रयोग चलते रहते हैं, जिसमें बच्चे परीक्षण साधन। और बिचारे सारे परीक्षण सफल होने के पहले धराशाई हो जाते हैं। अभी हाल ही में एक लेखक से उसकी रचनाओं में अंग्रेजी शब्दों की बहुतायतता पर प्रश्न किया गया। उनके द्वारा दिए गये उत्तर से मन प्रफुल्लित हो गया। उनके अनुसार - कई बार अंग्रेजी शब्द एक प्रवाह में बहकर चले आते हैं, इस प्रवाह को आप किसी नदी के प्रवाह की तरह देख सकते हैं। किसी नदी का अस्तित्व केवल उसके जल भर से नहीं है, उसमें समय समय पर अन्य नदियों का जल भी समाहित होता रहता है और वह नदी, एक विशाल रूप धारण कर लेती है, पर नदी का नाम नहीं बदलता, भाई हिन्दी हिन्दी ही रहेगी। बस यही कारण है कि रचना में अंग्रेजी शब्दों की उपस्थिति दिखाई देती है, जो यह बताती है कि लेखक निरा अनपढ़ नहीं है, वह अंग्रेजी भी जानता है। लेखक के अंग्रेजी जानने न जानने का मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि यदि इतनी अंग्रेजी आती है तो शुद्ध अंग्रेजी में ही लिखें। पर वे पीवर इंग्लिश में ही लिखना नहीं चाहते। उनका कहना है कि आज की परिस्थिति में भाषा को संक्रमण से बचाया जा नहीं सकता और देखो तो यह खिचड़ी कितनी शानदार है। बच्चों के लिए पौष्टिक भले न हो पर फ्राईड राइस से कम भी नहीं है। उन्हें तो यही भाता है।

विचार

चित्रा माली

सहायक प्रोफेसर, गांधी एवं शांति अध्ययन विभाग महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विवि क्षेत्रीय केंद्र,कोलकाता

यथार्थ की जमीन तलाशते मानव अधिकार

अधिकारों के संदर्भ में यदि महात्मा गांधी के विचारों का अनुसरण करें तो उनका स्पष्ट मत था कि 'अधिकारों का सच्चा स्रोत कर्तव्य है'। गांधी जी कहते हैं कि यदि हम सभी अपने कर्तव्यों का पालन उचित प्रकार से करें तो अधिकारों की प्राप्ति में कठिनाई नहीं होगी। किंतु यदि हम अपने कर्तव्यों को भूलकर अधिकारों के पीछे भागेंगे तो वे हमसे छलावे जैसा व्यवहार करेंगे और दूर भागते जाएंगे। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निर्वहन उचित प्रकार से करता है,उसे उसके अधिकारों की प्राप्ति स्वतः हो जाती है। प्रत्येक व्यक्ति अधिकारों पर बल देने के बजाय अपने कर्तव्यों का पालन करने लगे तो मानव जाति में तत्काल व्यवस्था स्थापित हो जाएगी। इस सरल और सार्वभौमिक नियम को हम मालिकों,मजदूरों, जमींदारों, काश्तकारों,पूंजीपतियों, हिंदू और मुसलमानों सभी पर लागू कर सकते हैं।

जिससे जन-जीवन और व्यवसाय में अव्यवस्था और उपद्रव किए बिना जीवन के सभी क्षेत्रों में मधुर संबंधों को स्थापित किया जा सकता है। गांधी जी के अनुसार यह सत्याग्रह का नियम है जिसका निगमन कर्तव्यों की समझ और अधिकारों के उनसे प्रवाहमान होने में निहित है। भारतीय संविधान में भी अधिकारों के साथ कर्तव्यों की अवधारणा का समावेश किया गया है। अस्सी के दशक में वैश्विक फलक पर मानवाधिकारों के मुद्दों के इर्द-गिर्द राजनीति में सक्रियता आयी। इसके विपरीत भारतीय संविधान उन सभी मूलभूत अधिकारों की गारंटी देता है जो संयुक्त राष्ट्र संघ की मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा में निहित है। भारतीय संविधान अपने पाठ में न केवल संयुक्त राष्ट्र संघ की उद्घोषणा का समावेश करता है,बल्कि अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक अधिकारों को बुलंद करने वाला वह दुनिया का पहला संविधान है। साथ ही राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांतों के तहत संविधान भविष्य में इन अधिकारों के विस्तार का प्रावधान भी करता है। भारत में मानवाधिकारों की अवधारणा को फलीभूत और विकसित करने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन भी किया गया है और राज्य सरकारों के स्तर पर राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन भी किया गया है। इसके अतिरिक्त 'राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग',अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग,तथा राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना भी की गई जिससे अल्पसंख्यकों के,अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण किया जा सके। 12 अक्टूबर 1993 में मानवाधिकार संरक्षा अधिनियम के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। यह एक स्वायत्त संस्था है जो दक्षिण एशियाई देशों में अनूठी है। इस के अनुच्छेद 2(1)(डी) में मानवाधिकारों की परिभाषा 'व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता,समानता और गरिमा के अधिकारों के रूप में करता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मानवाधिकारों के किसी भी उल्लंघन की जांच कर सकता है,किसी भी संबंधित मामले में अदालत की कार्रवाई में हस्तक्षेप कर सकता है,जेलों (कारागारों) का निरीक्षण कर सकता है, मानवाधिकारों से संबंधित राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संधियों की जांच कर सकता है,उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए केंद्र सरकार से सिफारिशें कर सकता है। मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र के तीस अनुच्छेदों और भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों में साम्य को देखा जा सकता है जिनमें जीवन की सुरक्षा, समानता,स्वतंत्रता,शोषण के विरुद्ध अधिकार का समावेश है। भारतीय संविधान के भाग तीन में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है जिन्हें पांच श्रेणियों में बांट कर देखा जा सकता है। पहली श्रेणी समानता के अधिकार की है जिसके अनुसार सभी को कानून के समक्ष समानता का अधिकार है। अवसरों की समानता के साथ साथ नस्ल, जाति, धर्म, लिंग और

जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव न करने की प्रतिबद्धता भी दर्ज की गई है। सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों,अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए विशेष सुविधाओं का प्रावधान भी है। मौलिक अधिकारों की दूसरी श्रेणी का संबंध स्वतंत्रता से है। जिसके तहत भारतीय संविधान अभिव्यक्ति,भाषण,विश्वास,धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करता है। साथ ही देश भर में निर्बाध रूप से घूमने,रहने और काम करने की स्वतंत्रता भी शामिल हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार किसी भी धर्म को मानने की उसकी पूजा पद्धति को मानने की और धर्म के प्रचार-प्रसार की भी स्वतंत्रता है। मौलिक अधिकारों की तीसरी श्रेणी जीवन के अधिकार से संबंधित है। कानून द्वारा स्थापित क्रियाविधि को छोड़कर किसी और तरीके से किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या निजी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 21 के मुताबिक भारतीय संविधान जीवन के अधिकार और निजी स्वतंत्रता को मानव अधिकार के स्तर पर ले जाता है। यह अधिकार नागरिकों को मनमानी नजरबंदी या गिरफ्तारी के खिलाफ सुरक्षा और कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार देता है। मौलिक अधिकारों की चौथी श्रेणी समूह या सामुदायिक अधिकारों की है। जिसमें अल्पसंख्यक समुदायों के लिए शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है, इसमें भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक समूहों को भी शामिल किया गया है। राज्य इन संस्थानों को आर्थिक मदद देने में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। मौलिक अधिकारों की पांचवी और बेहद महत्वपूर्ण श्रेणी न्यायिक समाधान की है।

इसके तहत मौलिक अधिकारों का हनन होने पर नागरिकों को न्यायालय की शरण में जाने का अधिकार देते है। भारतीय संविधान के भाग चार जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों सिद्धांत पर आधारित है इस हिस्से में भी मानव के लिए कई अधिकार दर्ज है : जैसे,मानवीय और न्यायसंगत परिस्थितियों में काम का अधिकार,न्यूनतम मजदूरी पाने का अधिकार, बेरोजगारी, वृद्धा अवस्था और बीमारी की स्थिति में सरकारी सहायता का अधिकार, चौदह साल तक के बच्चों के लिए अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा का अधिकार, प्रदूषण रहित पर्यावरण का अधिकार। भारतीय संविधान में प्रदत्त अधिकार और कर्तव्य व्यक्ति व समाज के समावेशी विकास के लिए आदर्श स्थिति को निर्मित करने का साधन है और वैश्विक स्तर पर न्याय और शांति स्थापित करने में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को साधन के तौर पर देखा जा सकता है लेकिन आज भी यह दोनों ही अपने साध्य से कोसों दूर है। नस्ल, धर्म,जाति,लिंग और क्षेत्र आधारित भेदभाव व भेदभाव जनित हिंसा, गैर-बराबरी,असमानता और शोषण हर जगह व्याप्त है जो न्यायपरक व्यवस्था के विरुद्ध है।

गैर-बराबरी,असमानता और भेदभाव के विरुद्ध हिंसात्मक संघर्ष युद्ध में परिवर्तित हो जाता है जो वैश्विक शांति के लिए खतरनाक साबित होता है। हम अपने देश की बात करें तो अभी हाल ही में एक व्यक्ति को उसके जीवन के अधिकार से महज इसलिए वंचित कर दिया गया क्योंकि वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था जिसे 'जय भीम' वाला कहकर संबोधित किया गया वह अपनी जाति से इतर दूसरी जाति की लड़की से प्रेम विवाह करने जा रहा रहा था जिसे लड़की के घर वालों ने मार डाला। अल्पसंख्यकों के साथ पेश आने का तरीका भी हमारा बहुत ही विचित्र है और कदम-कदम पर हम देश के प्रति उनकी निष्ठा को भी चेक करते रहते हैं। धर्म,जाति, लिंग, रंग और नस्ल के आधार पर भेदभाव के और मानवाधिकारों के हनन के कई उदाहरण हमारे सामने मौजूद हैं जो हमें बताते हैं कि हमारे अधिकारों और कर्तव्यों की समझ अभी भी ऊपरी तौर पर ही है उसे परिष्कृत और विकसित होने में और समय लगेगा। इसलिए आवश्यता है कि हम मानवाधिकार दिवस को महज एक दिवस के तौर पर न मानकर उसकी मूल अवधारणा जो मानव के अस्तित्व और गरिमा के लिए अनिवार्य है उसे आत्मसात करने का प्रयास करें।

राजनीति

जवाहर चौधरी

- लेखक साहित्यकार हैं

कांग्रेस : बड़ी चुनौती पार्टी को बनाए रखने की

सत्ता और संगठन के पास दीर्घकालिक लक्ष्य हैं। वे मानते हैं कि सत्ता साधन है, साध्य नहीं। धारा 370 हो या लंबे समय से विवादित राम मंदिर का मुद्दा, पार्टी ने अपने समय और शक्ति का उपयोग इस लक्ष्य को हासिल करने में किया। अपनी पार्टी को मज़बूत बनाने के लिए देशभर में आधुनिक तकनीकी सुविधाओं से युक्त पार्टी कार्यालय बनाए और वित्त व्यवस्था भी ग़ज़ब की सुदृढ़ की। इससे पार्टी में आत्मविश्वास और बढ़ा। जनता की धार्मिक भावना को ध्यान में रखते हुए तमाम मंदिर और तीर्थ स्थलों का विकास किया गया है। कुछ पर्यटन स्थल भी विकसित किए गए हैं। नई संसद भवन का निर्माण भी एक महत्वपूर्ण काम है। धर्म की गहरी जड़ों की पहचान कर, उसे अपने पक्ष में उपयोग करना एक राजनीतिक कौशल की तरह किया गया है।

कांग्रेस के सामने स्वयं को बनाए रखने की चुनौती है। यह ज़िम्मेदारी राहुल गांधी अकेले अपने कंधों पर उठाए दिखाई देते हैं, लेकिन इसे पूरी तरह प्रशंसनीय नहीं माना जा सकता है। उनके पास एक पुरानी, राष्ट्रीय और ऐतिहासिक पार्टी है, जिसमें तमाम नए-पुराने महत्वपूर्ण नेता मौजूद हैं। जमीनी स्तर पर ये तमाम नेता सक्रिय क्यों नहीं होते हैं? होना तो यह चाहिए कि सरकार के सभी विभागों के मंत्रियों की तरह, विपक्ष के पास भी उन पर निगरानी रखने के लिए समानांतर रूप से एक-एक समर्थ नेता हो। आखिर आप भी सरकार बनाने के लिए ही इतनी कवायद और दावेदारी कर रहे हैं, और जनता देख रही है। शक्ति को अपनी डाइनिंग टेबल तक सीमित करके बड़ी लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है।

कहते हैं, एक कुशल खिलाड़ी प्रतिद्वंद्वी को पहले अपने एरीना (मैदान) में लाता है और वहाँ अपनी शर्तों पर उसे लड़ने के लिए मजबूर करता है। नरेंद्र मोदी ज़मीनी अनुभव से पगे नेता हैं। उनके पास एक सशक्त राजनीतिक संगठन का सहयोग है। ख़ास बात यह है कि सत्ता और संगठन के पास दीर्घकालिक लक्ष्य हैं। वे मानते हैं कि सत्ता साधन है, साध्य नहीं। धारा 370 हो या लंबे समय से विवादित राम मंदिर का मुद्दा, पार्टी ने अपने समय और शक्ति का उपयोग इस लक्ष्य को हासिल करने में किया। अपनी पार्टी को मज़बूत बनाने के लिए देशभर में आधुनिक तकनीकी सुविधाओं से युक्त पार्टी कार्यालय बनाए और वित्त व्यवस्था भी ग़ज़ब की सुदृढ़ की। इससे पार्टी में आत्मविश्वास और बढ़ा। जनता की धार्मिक भावना को ध्यान में रखते हुए तमाम मंदिर और तीर्थ स्थलों का विकास किया गया है। कुछ पर्यटन स्थल भी विकसित किए गए हैं। नई संसद भवन का निर्माण भी एक महत्वपूर्ण काम है। धर्म की गहरी जड़ों की पहचान कर, उसे अपने पक्ष में उपयोग करना एक राजनीतिक कौशल की तरह किया गया है। परिणामस्वरूप, तमाम कथा आयोजन, प्रवचन, भजन-भंडारे, साधु-संत और उपदेशक उनके पक्ष में बोलते और काम करते दिखाई देते हैं। स्त्रियाँ ज़्यादा धार्मिक होती हैं और समझा जाता है कि उनमें अंधभक्त भी होती हैं। उनको इस स्थिति से उबारने की अपेक्षा अपने पक्ष में उपयोग करना फायदेमंद समझा गया। आज स्त्रियाँ भाजपा की बड़ी ताक़त हैं। मुस्लिम अपने ऐतिहासिक सांस्कृतिक मोह और सोच के चलते मुख्यधारा में घुल-मिल नहीं पाए। उनकी तमाम प्रवृत्तियों को राजनीतिक धरातल पर भाजपा ने एक सशक्त मुद्दा बनाने का प्रयास किया। अपराध, आतंकवाद, लव जिहाद और धर्म परिवर्तन जैसे मुद्दे प्रभावी बने। आम जन में भय का वातावरण बना और ध्रुवीकरण की जगह बनी। बावजूद इसके, मध्य प्रदेश से महिलाओं को नकद राशि बाँटने का प्रयोग किया, जो बाद में अन्य राज्यों को भी अपनाना पड़ा। बिहार में दस हज़ार एकमुश्त देकर सबसे चौंकाने वाली ख़बर भी बनी। चुनाव जीतने के लिए अब यह एक फ़ॉर्मूला बन गया लगता है।

लोकतंत्र में विपक्ष की रचनात्मक भूमिका होती है। असल में चौकीदार तो विपक्ष होता है। विपक्ष को आदर और सम्मान देना भारतीय लोकतंत्र की परंपरा

भी रही है। लेकिन भाजपा ने 'कांग्रेस मुक्त भारत' का आक्रामक लक्ष्य घोषित कर लोकतांत्रिक चुनावी व्यवस्था को युद्ध में बदल दिया। इसके जवाब में कांग्रेस को अपने मज़बूत इतिहास को रेखांकित करते हुए संगठित होना चाहिए था। भाजपा जानती है कि कांग्रेस का मज़बूत पक्ष क्या है, इसलिए बार-बार नेहरू को निशाने पर लिया जाता रहा है। मुख्य पिलर पर चोट करने से भवन जल्दी धराशायी हो जाता है। बुलडोज़र सिर्फ़ मकान पर ही नहीं चलते हैं। ज़रूरत पड़ जाए तो महापुरुष भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। दक्षिणपंथी विचारधारा उन्हें नायक मानने से संकोच करती है जो अंग्रेज़ों से लड़े। मुग़लों से जो लड़े, उन्हें नायक मानना उनकी राजनीतिक सुविधा भी है। सत्ता नेतृत्व जानता है कि कहाँ कांग्रेस निशस्त्र हो सकती है। सबसे बड़ी निशस्त्रता प्रगतिशील, समावेशी राजनीतिक विचारधारा के कारण है। गांधी जब ग्राम स्वराज की बात कर रहे थे, तब नेहरू ने उद्योग और वैश्विक मंच पर भारत को देखना चाहा। वे देश को आधुनिक संसार में देखना चाहते थे, ज़ाहिर है, बहुत सी चीज़ें छोड़नी पड़ीं। पश्चिम का अनुकरण हुआ - न केवल तकनीक में अपितु जीवन शैली, शिक्षा और संस्कृति में भी। इसके चलते जातिगत और धर्मगत नज़रियों पर शिथिलता बरती गई। आज की राजनीति में सांप्रदायिक मुद्दे और विचार जब भी उठाए जाते हैं, कांग्रेस राजनीतिक रूप से कमज़ोर पड़ने लगती है और उसे मुस्लिम परस्त बताते हुए घेर लिया जाता है। गोमांस जैसे संवेदनशील मुद्दों पर अनेक बार कांग्रेस को असहज होते देखा है। अस्सी करोड़ लोगों को मुफ़्त राशन देने का विरोध कोई भी पार्टी नहीं कर पा रही है। हर मौके पर कांग्रेस के मात्र चार चेहरे दिखाई देते हैं। प्रतीत होता है, कांग्रेस नेतृत्व अपने लोगों का उपयोग नहीं कर पा रहा है। यदि कोई दल है, तो दल दिखना भी चाहिए। कांग्रेस को मिशन मोड में रहने वाली भाजपा से भी सीखने की ज़रूरत है। उसके महत्वपूर्ण नेता या तो खामोश बैठे हैं या फिर पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। उन्हें पार्टी में रोक रखने की कोशिश दिखाई नहीं देती। होना तो यह चाहिए था कि वे ज़मीनी स्तर पर कोई मज़बूत संगठन बनाने का प्रयास करते। आरएसएस की तरह का संगठन बना लेना कांग्रेस के बूते का नहीं है। लेकिन केवल सरकार से असंतोष और बिखरे हुए लोगों के भरोसे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। लगता है कांग्रेस के पुरातन पेड़ पर एकतरफ़ा पतझर चल रहा है। आज कुछ जगहों पर कांग्रेस की सभाओं में भीड़ दिखाई दी है, लेकिन इस भीड़ को वोट में बदलना बहुत बड़ी चुनौती है। लगता है, कांग्रेस के समक्ष सरकार बनाने की चुनौती तो नहीं है, बड़ी चुनौती पार्टी को बनाए रखने की है।

आबादी के समीकरण

अरुण कुमार डनायक

लेखक सामाजिक कार्यकर्ता हैं ।

बदलती वैश्विक जनसांख्यिकी की दिशा

भारत आज दुनिया का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है और लगभग 1.45 अरब की आबादी के साथ उसने चीन को पीछे छोड़ दिया है। बीते दशकों में ग्रामीण क्षेत्रों की जन्म दर, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ और बढ़ती जीवन प्रत्याशा इसकी प्रमुख वजह रही हैं। लेकिन बढ़ती आबादी के साथ शहरों पर दबाव, सीमित रोज़गार, शिक्षा-स्वास्थ्य सेवाओं पर बढ़ता बोझ और संसाधनों की कमी जैसी चुनौतियाँ भी सामने हैं। इसके बावजूद भारत की विशाल युवा आबादी उसकी सबसे बड़ी ताकत है, जो सही नीतियों के साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था को दिशा दे सकती है। साथ ही, देश की कुल प्रजनन दर घटकर 1.9 पर आना एक महत्वपूर्ण बदलाव है–कम बच्चों के कारण महिलाओं के पास शिक्षा, कौशल और आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी के अधिक अवसर होंगे, जिससे उत्पादनशीलता और आर्थिक विकास को गति मिल सकती है।

मानव इतिहास में जनसंख्या हमेशा चुनौतियों और अवसरों दोनों की धुरी रही है। आज जब दुनिया की आबादी 8 अरब के पार पहुँच चुकी है, तब वैश्विक जनसांख्यिकी पहले से कहीं अधिक जटिल और परिवर्तनशील हो गई है। तकनीकी प्रगति, बेहतर जीवन स्तर और स्वास्थ्य सुविधाओं ने इस बदलाव को नई दिशा दी है। 2025 की जनसंख्या रैंकिंग इसी परिवर्तन का संकेत है, जिसमें भारत, चीन, अमेरिका, इंडोनेशिया और पाकिस्तान वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले प्रमुख देश बनकर उभरे हैं।

भारत आज दुनिया का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है और लगभग 1.45 अरब की आबादी के साथ उसने चीन को पीछे छोड़ दिया है। बीते दशकों में ग्रामीण क्षेत्रों की जन्म दर, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ और बढ़ती जीवन प्रत्याशा इसकी प्रमुख वजह रही हैं। लेकिन बढ़ती आबादी के साथ शहरों पर दबाव, सीमित रोज़गार, शिक्षा-स्वास्थ्य सेवाओं पर बढ़ता बोझ और संसाधनों की कमी जैसी चुनौतियाँ भी सामने हैं। इसके बावजूद भारत की विशाल युवा आबादी उसकी सबसे बड़ी ताकत है, जो सही नीतियों के साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था को दिशा दे सकती है। साथ ही, देश की कुल प्रजनन दर घटकर 1.9 पर आना एक महत्वपूर्ण बदलाव है–कम बच्चों के कारण महिलाओं के पास शिक्षा, कौशल और आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी के अधिक अवसर होंगे, जिससे उत्पादनशीलता और आर्थिक विकास को गति मिल सकती है।

चीन, जिसने दशकों तक दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश होने का गौरव रखा, आज जनसंख्या वृद्धि की उलटी दिशा में बढ़ रहा है। लगभग 1.42 अरब की आबादी के बावजूद वहाँ जन्म दर तेजी से गिर रही है। 1979 से 2015 तक लागू रही एक-बच्चा नीति के कारण आज चीन असंतुलित आयु संरचना, तेज़ी से बढ़ती वृद्ध आबादी और लैंगिक असमानता जैसी चुनौतियों से जूझ रहा है। हालाँकि सरकार अब परिवार विस्तार को प्रोत्साहित कर रही है, पर सामाजिक-आर्थिक बदलावों ने छोटे परिवार की प्रवृत्ति को मजबूत कर दिया है। इसका सीधा असर चीन की विशाल श्रम शक्ति और उसके विनिर्माण-केंद्रित आर्थिक मॉडल पर पड़ने वाला है।

अमेरिका लगभग 33.5 करोड़ की आबादी के साथ जनसंख्या के मामले में तीसरे स्थान पर है। इसकी जनसांख्यिकीय विविधता और जनसंख्या वृद्धि का मुख्य आधार जन्म दर नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय प्रवासन है। यही प्रवासन तकनीक, शिक्षा, उद्योग और सेवा क्षेत्रों में उसकी आर्थिक गतिशीलता को मजबूती देता है। हालांकि बदलती राजनीतिक परिस्थितियों में आव्रजन नीतियों में होने वाले बदलाव भविष्य की अमेरिकी जनसंख्या संरचना को गहराई से प्रभावित कर सकते हैं।

इंडोनेशिया, लगभग 27.5 करोड़ की आबादी के साथ दुनिया का चौथा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। हजारों द्वीपों में फैले इस देश में जावा जैसे अत्यंत घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य सुधार से जन्म दर में कमी आई है, फिर भी विशाल युवा आबादी के कारण रोज़गार और बुनियादी ढांचे पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। पाकिस्तान, 24 करोड़ से अधिक आबादी के साथ पाँचवें स्थान पर है और यहाँ दुनिया की सबसे तेज़ जनसंख्या वृद्धि दरों में से एक है। अत्यधिक युवा आबादी विकास की संभावना भी है और बड़ी चुनौती भी। तेज़ शहरीकरण के कारण जल, ऊर्जा, आवास और रोजगार जैसी समस्याएँ लगातार गंभीर होती जा रही हैं। दुनिया की जनसंख्या संरचना को प्रभावित करने वाले कई कारक समानांतर रूप से कार्य कर रहे हैं। जन्म दर में अंतर, आर्थिक अवसर, सामाजिक प्रवृत्तियाँ, शिक्षा का प्रसार, स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और लंबे समय तक लागू रहने वाली सरकारी नीतियाँ इन कारकों का हिस्सा हैं। प्रवासन आज आधुनिक दुनिया की जनसंख्या को आकार देने वाली एक निर्णायक शक्ति बन चुका है। बेहतर शिक्षा, सुरक्षित जीवन, आर्थिक अवसर और जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न विस्थापन ने इसे वैश्विक प्रक्रिया में बदल दिया है। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अनेक यूरोपीय देश अपनी जनसंख्या और श्रम शक्ति को संतुलित रखने के लिए प्रवासन पर निर्भर हैं, जबकि आर्थिक संकट से जूझ रहे देशों से युवाओं का पलायन लगातार बढ़ रहा है। वहीं अवैध प्रवासन सुरक्षा, सामाजिक स्थिरता और प्रशासन के सामने नई और गंभीर चुनौतियाँ खड़ी कर रहा है।

विकसित देशों में वृद्ध होती आबादी एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी और इटली जैसे देशों में कामकाजी आयु वर्ग घट रहा है, जबकि बुजुर्गों की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है। इससे स्वास्थ्य सेवाओं, पेंशन और सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था पर भारी दबाव पड़ रहा है। जन्म दर बढ़ाने के लिए सरकारी प्रयास हो रहे हैं, लेकिन सामाजिक बदलाव इन्हें सीमित प्रभाव ही दे पा रहे हैं।

आर्थिक दृष्टि से बड़ी जनसंख्या एक दोधारी तलवार है। एक ओर विशाल श्रम शक्ति और बड़ा घरेलू बाज़ार आर्थिक विस्तार को गति देता है, वहीं दूसरी ओर पर्याप्त रोज़गार, कौशल और संसाधन न होने पर बेरोज़गारी, असमानता और सामाजिक तनाव बढ़ता है। साथ ही, बढ़ती आबादी के लिए मजबूत अवसंरचना, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा और जल प्रबंधन की आवश्यकता भी अत्यंत चुनौतीपूर्ण हो जाती है।

2050 तक दुनिया की जनसंख्या संरचना में बड़े बदलाव तय माने जा रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दशकों में अफ्रीका वैश्विक जनसंख्या वृद्धि का मुख्य केंद्र बनेगा, जहाँ नाइजीरिया, इथियोपिया और कांगो जैसे देशों की आबादी तेज़ी से बढ़ेगी। एशिया में भारत की जनसंख्या वृद्धि धीमी होते हुए स्थिरता की ओर बढ़ेगी, जबकि चीन की आबादी घटने लगेगी। यूरोप पहले ही जनसंख्या गिरावट के दौर में प्रवेश कर चुका है, वहीं अमेरिका प्रवासन-आधारित मॉडल के सहारे जनसंख्या संतुलन बनाए रखेगा। 2025 की जनसंख्या रैंकिंग इस बात का संकेत है कि दुनिया एक नई जनसांख्यिकीय व्यवस्था की ओर बढ़ रही है। अब वैश्विक शक्ति-संतुलन का निर्धारण अब केवल अर्थव्यवस्था और सैन्य क्षमता से नहीं, बल्कि जनसंख्या संरचना से भी होगा। युवा आबादी वाले राष्ट्र आने वाले समय में विकास, नवाचार और उत्पादन के नए केंद्र बन सकते हैं, जबकि वृद्ध होती जनसंख्या वाले देशों के सामने सामाजिक सुरक्षा, श्रम शक्ति और आर्थिक स्थिरता की जटिल चुनौतियाँ होंगी। जलवायु परिवर्तन, बढ़ता प्रवासन और सीमित होते प्राकृतिक संसाधन इन चुनौतियों को और गहरा बना रहे हैं। ऐसे समय में जनसंख्या को बोझ नहीं, बल्कि सुनियोजित नीतियों, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के माध्यम से एक सशक्त राष्ट्रीय पूंजी में बदलना ही 21वीं सदी की सबसे बड़ी प्रशासनिक और राजनीतिक परीक्षा होगी। इस बदलते परिदृश्य में भारत को भी शिक्षा, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण और रोजगार सृजन को जनसंख्या नीति का केंद्र बनाने तैयारियां करनी होंगी !

भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष पवन पाटीदार का पहली बार धार आगमन पर भव्य स्वागत हुआ

भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो छोटे से छोटे कार्यकर्ता को योग्यतानुसार बड़े से बड़े पद पर सुशोभित करती है : पवन पाटीदार

धार । भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पवन पाटीदार का पहली बार शुक्रवार को धार आगमन पर भव्य स्वागत किया गया। भाजपा जिला कार्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में पिछड़ा वर्ग के प्रबुद्धजनों को शाल श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। सर्व प्रथम भारत माता व पितृ पुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्रों पर माल्यार्पण दीप प्रज्जवलित कर आरंभ किया।

इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष महंत निलेश भारती, विधायक श्रीमती नीना वर्मा ,मोर्चा जिला अध्यक्ष निलेश राठोड़ ने कार्यकर्ताओ को संबोधित किया। मंच पर जिला पंचायत अध्यक्ष सरदार सिंह मेड़ा, मोर्चा प्रदेश मंत्री धीरज पाटीदार, मोर्चा प्रदेश सह मीडिया प्रभारी नरेंद्र राठौर, भाजपा जिला महामंत्री देवेंद्र सोनोने भाजपा जिला मीडिया प्रभारी संजय शर्मा, मंडल अध्यक्ष जयराज देवड़ा, मोर्चा जिला महामंत्री अनिल गेहलोद, कन्हैयालाल गुर्जर उपस्थित रहे।

भाजपा के जिलाध्यक्ष महंत निलेश भारती ने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के गांव, गरीब और नौजवान तक पहुंच रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य हर व्यक्ति के चेहरे पर खुशहाली लाना है तथा गरीबों के

जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीबों और वंचितों की सेवा के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं और मध्यप्रदेश सरकार भी अंत्योदय की भावना को आधार बनाकर आगे बढ़ रही। गरीबों की सेवा ही भाजपा सरकार का प्रमुख संकल्प है। इसी दिशा में योजनाएं चलाई जा रही हैं।

विधायक नीना वर्मा ने कहा कि बीजेपी सरकार में महिलाओं को विशेष सम्मान मिला है। महिलाओं की समस्या महिलाएं ही समझती हैं। महिलाएं राजनीति में आगे आएंगी तो समस्याएं अपने आप ही हल हो जाएंगी। भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें सभी लोगों को एक समान रखा जाता है। पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का विकास करना ही भाजपा का लक्ष्य है। भाजपा ऐसी पार्टी है जो लोगों का दुख दर्द समझती है। धार में मेडीकल कॉलेज का शिलान्यास होगा। यह हमारे लिए बड़ी सौगात है। 23 दिसंबर को इसका भुमिपूजन होगा।

पिछड़ा वर्ग मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष पवन पाटीदार ने कहा कि भाजपा ही एक मात्र ऐसी पार्टी है जो छोटे से छोटे कार्यकर्ता को योग्यतानुसार बड़े से बड़े पद पर सुशोभित करती है पवन पाटीदार इसका जीता जागता उदाहरण है। प्रत्येक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है कि केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पिछड़े वर्ग के लोगों तक पूरी ईमानदारी से पहुंचाया जाए। धार के बदनावर में स्थापित हो रहा पीएम मित्रा पार्क रोजगार के साथ किसानों के लिए वरदान साबित होगा। कपास की खेती से लाभ मिलेगा। उन्होंने दावा किया कि भाजपा ने कांग्रेस की तुलना में प्रदेश और केंद्र में ओबीसी वर्ग को अधिक प्रतिनिधित्व दिया है। पाटीदार ने कहा कि भाजपा की नीति हर वर्ग के उत्थान और विकास की स्पष्ट है और कांग्रेस केवल जुमलेबाजी करती है। भाजपा सरकार गुलामी का हर प्रतीक हटाकर पुनः भारत का इतिहास बदलने का दम रखती है। पिछड़ा वर्ग के कार्यकर्ता सक्रियता के साथ काम कर पार्टी को मजबूती प्रदान करे। कार्यक्रम में पिछड़ा वर्ग के विभिन्न समाजों से आए हुए प्रमुख लोगो का अतिथि द्वारा शाल श्रीफल भेंटकर पुष्पमाला पहनाकर सम्मान किया गया। पिछड़ा वर्ग मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष पवन पाटीदार का धार नगर आगमन पर नगर के विभिन्न समाज और मोर्चा द्वारा स्वागत मंच लगाकर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। संचालन अनिल गेहलोद ने किया। जानकारी भाजपा जिला मीडिया प्रभारी संजय शर्मा ने दी।

माधवराव सप्रे शासकीय महाविद्यालय में पं. माधवराव सप्रे की प्रतिमा का अनावरण

पथरिया। पथरिया के माधवराव सप्रे शासकीय महाविद्यालय में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, साहित्यकार एवं पत्रकारिता के पुरोधा पंडित माधवराव सप्रे की प्रतिमा का अनावरण किया गया। वक्ताओं ने कहा कि पथरिया में जन्मे सप्रे जी हिंदी नवजागरण के प्रमुख स्तंभ रहे हैं और उन्होंने 'एक टोकरी भर मिट्टी' जैसी पहली हिंदी कहानी लिखकर साहित्य को नई दिशा दी।

मंत्री श्री सारंग ने किया गोकुलधाम एवं द्वारकाधाम कॉलोनी की विद्युत समस्या का निराकरण

वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर दिये निर्देश

भोपाल। सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने नरेला विधानसभा अंतर्गत गोकुलधाम एवं द्वारकाधाम कॉलोनियों में लंबे समय से चली आ रही विद्युत आपूर्ति संबंधी समस्याओं के निराकरण हेतु जिला प्रशासन एवं संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित कर वस्तुस्थिति की समीक्षा की तथा आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किये। बैठक में कलेक्टर भोपाल श्री कौशलेंद्र सिंह, नगर निगम आयुक्त श्रीमती संस्कृति जैन, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी, भोपाल के प्रबंध संचालक श्री क्षितिज सिंघल सहित जिला प्रशासन, विद्युत विभाग के वरिष्ठ अधिकारी एवं दोनों कॉलोनियों के रहवासी उपस्थित रहे।

बैठक में अवगत कराया गया कि दिनांक 29 नवंबर 2024 को लिये गये निर्णयों के उपरांत भी अपेक्षित प्रगति नहीं हो सकी है। द्वारकाधाम कॉलोनी में रहवासियों द्वारा रू. 17 लाख की राशि जमा कर दी गई है, किंतु बिल्डर द्वारा शेष रू. 39 लाख का भुगतान नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान में कुल बकाया विद्युत बिल रू. 53 लाख हो गया है। इसके अतिरिक्त, द्वारकाधाम कॉलोनी के वर्तमान विद्युत बिलों के अंतर्गत लगभग रू. 15 लाख की राशि अभी भी शेष बतायी गई है, यद्यपि रहवासियों द्वारा समय-समय पर भुगतान किया जाता रहा है। गोकुलधाम कॉलोनी के संबंध में बताया गया कि पिछली बैठक के समय कुल बकाया राशि 72 लाख थी, जिसमें से रहवासियों को 5 मासिक किश्तों में 28 लाख तथा बिल्डर को 44 लाख जमा करना था। अभी तक न तो रहवासियों द्वारा और न ही बिल्डर द्वारा कोई भी राशि जमा की गई है। वर्तमान विद्युत बिलों के साथ यह बकाया राशि जुड़कर कुल लगभग 1.27 करोड़ हो चुकी है। गोकुलधाम कॉलोनी के संबंध में निर्देश दिये गये कि कॉलोनीवासियों एवं मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, भोपाल के मध्य परस्पर सहमति के आधार पर दिनांक 31 दिसंबर 2025 तक विद्युत देयकों की कुल देय राशि का 50 प्रतिशत भाग कॉलोनीवासियों एवं बिल्डर द्वारा जमा कराया जायेगा। उक्त राशि के जमा होने के उपरांत कॉलोनी की विद्युत समस्या के निराकरण हेतु मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, भोपाल द्वारा आवश्यक कार्यादेश (वर्क ऑर्डर) जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जायेगी।

विन्ध्य को देश का बेहतर क्षेत्र बनाने की संकल्पना है: राजेन्द्र शुक्ल

विन्ध्य गौरव सम्मान – विन्ध्य में पंचायत कार्यक्रम में शामिल हुए उप मुख्यमंत्री

भोपाल। उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि विन्ध्य को देश का बेहतर क्षेत्र बनाने की संकल्पना के साथ कार्य कराये जा रहे हैं। विकास कार्यों के साथ-साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग रोजगार आदि क्षेत्रों में यह क्षेत्र अग्रणी बनने की ओर अग्रसर है। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने विन्ध्य की विभूतियों को गौरव सम्मान से सम्मानित किया।

टी.बी. चैनल विस्तार के विन्ध्य गौरव सम्मान - विन्ध्य म पंचायत कार्यक्रम में रूबरू होते हुए उप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि गत दस वर्षों में विन्ध्य की तस्वीर बदली है। केन्द्र व राज्य सरकार के सहयोग से यहाँ विभिन्न क्षेत्रों में अनेक कार्य हुए हैं और अब यह क्षेत्र अग्रणी क्षेत्र के तौर पर जाने जाना लगा है। उन्होंने कहा कि रीवा व विन्ध्य में सीमेंट, पावर, वाइल्डलाइफ, पर्यटन के साथ ही धार्मिक स्थल हैं। कनेक्टिविटी हो जाने से विकास और बढ़ा है। रीवा से दिल्ली के लिये वायुसेवा शुरू हो गई है। अब तक रीवा से 850 यात्री व दिल्ली से 840 यात्री वायुयान में यात्रा कर चुके हैं। आगामी 22 दिसंबर से रीवा-इंदौर की नियमित वायुसेवा आरंभ हो रही है। हमारी संकल्पना है कि रीवा एयरपोर्ट से एयरबस प्रारंभ हो इसके लिये एयरपोर्ट विस्तार का कार्य भी किया जायेगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर व विकसित भारत का सपना स्वस्थ्य नागरिकों के आधार पर ही पूरा होगा इस उद्देश्य से स्वास्थ्य सेवाओं में निरंतर वृद्धि की जा रही है। रीवा सहित प्रदेश के पांच पुराने मेडिकल कालेज व उनसे संबंद्ध चिकित्सालयों के नवीन भवन निर्मित किये जा रहे हैं। आगामी दिनों में बाणसागर की नहरों से रीवा की एक एक इंच भूमि सिंचित हो जायेगी और यह क्षेत्र अग्रणी होगा। उन्होंने बताया कि किसानों को प्राकृतिक खेती करने के लिये जागरूक किया जा रहा है। बसामन मामा गौवंश वन्य बिहार में 10 हजार गौवंश संरक्षित हैं। वहां प्राकृतिक खेती केन्द्र स्थापित कर प्रशिक्षण भी प्रारंभ किया गया है। प्रदेश के गृह मंत्री श्री अमित शाह आगामी 25 दिसंबर को किसान सम्मेलन व प्राकृतिक खेती कार्यक्रम में शामिल होंगे तथा गौ उत्पादों का निरीक्षण करेंगे। श्री शाह 25 दिसंबर को ही रीवा में श्री अटल बिहारी बाजपेयी जी की प्रतिभा का भी अनावरण करेंगे। कार्यक्रम में चैनल के बृजेश राजपूत ने उप मुख्यमंत्री जी से संवाद किया। इस दौरान ज्ञानेन्द्र तिवारी, अंचल शुक्ला, श्वेता जी, अपूर्वा जी सहित शहर के गणमान्य नागरिक तथा बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे।

उप मुख्यमंत्री ने लक्ष्मणबाग के पुजारियों व अन्य कर्मचारियों को कंबल वितरित किये

उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने लक्ष्मणबाग में पुजारियों एवं आचार्यों को कंबल वितरित किये। उन्होंने लक्ष्मणबाग गौशाला में कार्यरत कर्मचारियों को कंबल का वितरण किया। भारतीय रेडक्रास सोसायटी इकाई रीवा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में रेडक्रास सोसायटी के चेयरमैन डॉ. प्रभाकर चतुर्वेदी, डॉ. राजेश मिश्रा उपस्थित रहे।

'खेलों से धैर्य और संजीदगी से कार्य करने की प्रेरणा मिलती है'

उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि खेलों से धैर्य और संजीदगी से कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। खेल के मैदान की खेल भावना जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करती है। श्री शुक्ल ने पशु चिकित्सा महाविद्यालय रीवा में 18वीं वार्षिक इंटरक्लास खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। उन्होंने खिलाड़ियों को शपथ दिलाकर तथा मशाल प्रज्जवलित का प्रतियोगिता का शुभारंभ किया।

पशु चिकित्सा महाविद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल हमें अंतरिक शक्ति देते हैं तथा खेल के मैदान से मिली सीख हमारे व्यक्तित्व को निखारती है। उन्होंने कहा कि खेलों में भाग लेने वाले प्रतिभागी हारने वाले को भी बधाई देकर आगे बढ़ने की कामना करता है। खेल के मैदान में मानव के अवगुण जैसे ईर्ष्या, द्वेष व जलन खेल भावना के कारण दूर हो जाती है और सभी खिलाड़ी आपस में भाईचारे के साथ खेलों में भाग लेते हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मनुष्य का जीवन पशुधन के बिना अधूरा है। पशु चिकित्सा महाविद्यालय के छात्र पढ़ाई के साथ-साथ खेल व अन्य गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं यह प्रशंसनीय है। उन्होंने विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि वह हर क्षेत्र में आगे बढ़े और विकसित भारत के निर्माण में सहभागी बनें। इससे पूर्व पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय के कुलगुरू मनदीप शर्मा ने स्वागत उद्बोधन में कहा कि उप मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से ही रीवा ने हर क्षेत्र में प्रगति की है। उन्होंने कहा कि खेलों से हमें अनुशासन और टीम भावना की सीख मिलती है। खेलों में भाग लेना जरूरी है हार और जीत खेल के हिस्से हैं। प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने शानदार मार्च पास्ट की प्रस्तुति दी घुड़सवार छात्रों ने घुडसवारी का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।

रीवा से इंदौर के लिये नियमित विमान सेवा का 22 दिसंबर को होगा शुभारंभ

रीवा से इंदौर के लिये एटीआर 72 विमान 22 दिसंबर को उड़ान भरेगा। इंडिगो एयरलाइंस की इस नियमित सेवा में वायुयान दोपहर बाद 1.15 बजे रीवा आयेगा तदुपरांत 1.35 बजे इंदौर रवाना होगा। उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने 22 दिसंबर को आयोजित होने वाले शुभारंभ कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया तथा सभी व्यवस्थायें दुरूस्त रखने के निर्देश संबंधितों को दिये। उन्होंने बताया कि नगरीय प्रशासन मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय अपने 40 से अधिक सदस्यीय दल के साथ इंदौर से रीवा आयेंगे। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल स्वयं इस विमान से 70 से अधिक यात्रियों के साथ इंदौर रवाना होंगे। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि रीवा से नई दिल्ली विमान सेवा के बेहतर परिणाम सामने आये हैं। इसको देखते हुए एलायंस एयर अब रविवार को भी नई दिल्ली से रीवा व रीवा से नई दिल्ली के लिये विमान का संचालन करने की कार्यवाही कर रहा है। बैठक में नगर निगम अध्यक्ष व्यंकटेश पाण्डेय, विधायक प्रतिनिधि विवेक दुबे, के.के. गर्ग, बालेन्द्र गौतम सहित इंडिगो के अधिकारी, रीवा एयरपोर्ट के अधिकारी शुभम शर्मा उपस्थित रहे।

नाबालिग हत्या केस में पुलिस का सख्त एक्शन

मुख्य आरोपी के पिता और साथी का कान पकड़वाकर शहर में निकाला जुलूस

बैतूल। नाबालिग विवेक मरकाम की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। शुक्रवार को पुलिस ने मुख्य आरोपी अन्नू ठाकुर, उसके पिता कृपाल ठाकुर और साथी जुनैद का जुलूस निकाला। तीनों को अन्नू के घर चुन्नीढाना से गंज के व्यस्त इलाके और कोठीबाजार के मुख्य मार्गों पर कान पकडक़र घुमाया गया। इस दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहा और राहगीरों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस सनसनीखेज हत्या प्रकरण में पुलिस ने अब तक अन्नू ठाकुर, पिता कृपाल ठाकुर, जुनैद और दो नाबालिगों को गिरफ्तार किया है, जबकि तीन

आरोपी अब भी फरार हैं। सभी गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया। जानकारी के अनुसार बुधवार दोपहर 17 वर्षीय विवेक मरकाम की चुन्नीढाना क्षेत्र में बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी। आरोपी उसे सागौन बाबा दरबार से अगवा कर वहां ले गए थे। विवेक की मौत के बाद पूरे क्षेत्र में आक्रोश फैल गया था। गिरफ्तार अन्नू और जुनैद को भारत भारती क्षेत्र से पकड़ा गया, जबकि कृपाल ठाकुर को उसके घर से हिरासत में लिया गया। फरार आरोपियों में रोहित और अभिषेक ठाकुर (अन्नू के भाई) समेत तीन लोगों की तलाश जारी है। कुल सात लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। जांच में सामने आया है कि मृतक विवेक और अन्नू ठाकुर के बीच पुराना विवाद था। भगूढाना में गाड़ी टकराने के विवाद के बाद विवेक ने अन्नू पर चाकू से हमला किया था। बाद में अन्नू ने विवेक के घर जाकर भी हमला किया था, लेकिन तब मामला दर्ज नहीं हुआ। दोनों ही जमानत पर थे। पुलिस ने बताया कि प्राथमिक पूछताछ में आरोपियों ने माना कि विवेक बार-बार उन्हें धमका रहा था, इसी रंजिश में उसने वारदात को अंजाम दिया। घटना में प्रयुक्त रॉड, डंडे और फावड़े बरामद कर लिए गए हैं। मृतक विवेक की मां शिक्षिका हैं और पिता वन विभाग में कार्यरत हैं।

पीपीपी मोड पर बैतूल को मिलेगी मेडिकल कॉलेज की सौगात

उत्कृष्ट उपचार के साथ मिलेगी मेडिकल एजुकेशन की सुविधा

बैतूल। जिले के लिए यह खबर किसी बड़ी सौगात से कम नहीं है। लंबे समय से मेडिकल कॉलेज की मांग कर रहे बैतूलवासियों का सपना अब साकार होने जा रहा है। बैतूल जिले में पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज की शुरुआत की जाएगी। बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल के प्रयासों का ही परिणाम है कि जिले की स्वास्थ्य सेवाओं और मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में एक नए युग का आगाज होगा। पीपीपी मॉडल के तहत सरकार और निजी क्षेत्र की साझेदारी से मेडिकल कॉलेज का संचालन किया जाएगा। इससे आधुनिक तकनीक, बेहतर प्रबंधन और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं सुनिश्चित होंगी। बैतूल जिले के कोसमी क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। सुपर स्पेशलिटी विभागों की शुरुआत होगी, जिससे गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए मरीजों को भोपाल, नागपुर या इंदौर जैसे बड़े शहरों की ओर रुख नहीं करना पड़ेगा। विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता से हृदय रोग, हड्डी रोग, स्त्री एवं शिशु रोग, सर्जरी सहित अन्य विभागों में बेहतर उपचार संभव हो सकेगा।

ग्रामीण अंचल को मिलेगा सबसे अधिक लाभ- बैतूल जिला जनजातीय और ग्रामीण बहुल क्षेत्र है। यहां के लोगों को अक्सर संसाधनों की कमी के कारण समय पर इलाज नहीं मिल पाता। मेडिकल कॉलेज खुलने से ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के मरीजों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा जिले में ही मिलेगी। इससे मातृ-शिशु मृत्यु दर में कमी आने और स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार की उम्मीद है। पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना से जिले के विद्यार्थियों को मेडिकल की पढ़ाई के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा।

अग्रवाल युवक- युवती परिचय सम्मेलन में 500 से अधिक प्रविष्टियां प्राप्त

युवक–युवती परिचय सम्मेलन धार स्थित श्रद्धा शगुन गार्डन में 10 एवं 11 जनवरी को

धार। मध्यप्रदेश अग्रवाल महासभा धार द्वारा अग्रवाल समाज धार के सानिध्य में होने वाले दो दिवसीय अखिल भारतीय अग्रवाल युवक-युवती परिचय सम्मेलन धार स्थित श्रद्धा शगुन गार्डन में 10 एवं 11 जनवरी को होगा। सम्मेलन के लिए विशेष बात यह है कि शुक्रवार तक 500 से अधिक युवक एवं युवतियों की प्रविष्टियां प्राप्त हो चुकी हैं जिसमे युवतियों की बड़ी संख्या में इंटी प्राप्त हुई। 500 प्रविष्टियां प्राप्त होने पर कार्यालय पर ढोल धमाके आतिशबाजी मिठाई वितरण कर खुशी मनाई। यह आयोजन की सफलता का एक अच्छा संकेत है, क्योंकि यह दर्शाता है कि बड़ी संख्या में लोग इस सम्मेलन में रुचि ले रहे हैं। प्रतिभागियों के लिए भी अच्छी खबर है, क्योंकि जितनी अधिक प्रविष्टियां होंगी, संभावित उपयुक्त जीवन साथी मिलने की संभावना उतनी ही अधिक होगी।

परिचय सम्मेलन से प्रत्याशियों और अभिभावकों को एक ही स्थान पर अलग-अलग शहरों के युवक-युवतियों को जानने और समझने

का मौका मिलेगा। प्रविष्टियां की अंतिम दिनांक 25 दिसंबर है। मीडिया प्रभारी अशोक मित्तल एवं श्याम मंगल लेबड़ ने बताया कि सम्मेलन में प्राप्त हुई इंट्री में अधिकांश डॉक्टर, इंजीनियर, एमबीए, सीए, एमसीए जैसे उच्च शिक्षित एवं स्वयं के रोजगार में स्थापित उद्योगपति एवं व्यापारी प्रत्याशी शामिल हैं। बाहर से आने वाले प्रत्याशियों और अभिभावकों के लिए ठहरने की व्यवस्था भी की जाएगी। सम्मेलन स्थल पर कम्प्यूटर से कुंडली मिलान, पंडितजी, ज्योतिषी से कुंडली एवं गुण मिलान, अभिभावक चर्चा कक्ष और युवक-युवती चर्चा कक्ष भी बनाए जाएंगे। समाजजन धार में भी घर-घर जा रहे हैं और आसपास के क्षेत्र का भी दौरा कर रहे हैं।

एनएच-347 ए भूमि अधिग्रहण को लेकर प्रभातपट्टन क्षेत्र में किसानों में रोष

उचित मुआवजा नहीं मिला तो होगा आंदोलन

बैतूल / मुलताई। मध्य प्रदेश को महाराष्ट्र से जोडऩे वाले मुलताई-गौनापुर-वरुण-महाराष्ट्र बॉर्डर मार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच-347 ए) के चौड़ीकरण के लिए किए गए भूमि अधिग्रहण को लेकर प्रभातपट्टन क्षेत्र के किसानों में भारी असंतोष व्याप्त है। इस संबंध में किसानों ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 48 के अंतर्गत मुलताई के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी के न्यायालय में विधिवत आपत्ति पत्र प्रस्तुत किया है। किसान सोनू, अजय एवं मनोहर सहित अन्य प्रभावित किसानों ने आपत्ति पत्र में बताया कि तहसील प्रभातपट्टन के ग्राम प्रभातपट्टन में एनएच-347 ए के दो लेन विद पेवर्ड शोल्डर निर्माण के लिए निजी भूमि का अधिग्रहण किया गया है, जिसका अधिनिर्णय 23 सितंबर 2025 को पारित किया गया था। किसानों का आरोप है कि यह भूमि अधिग्रहण असमान, अन्यायपूर्ण एवं पक्षपातपूर्ण है, जिसे वे स्वीकार नहीं करते। किसानों ने बताया कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में काश्तकारों एवं भूमि धारकों की भूमि अलग-अलग मात्रा में ली गई है, जिससे कहीं कम तो कहीं अत्यधिक भूमि अधिग्रहित हुई है। साथ ही अधिग्रहित

भूमि में सागौन के पेड़, फलदार वृक्ष, कुएं, ट्यूबवेल तथा उपजाऊ एवं सिंचित कृषि भूमि शामिल है, जिनका मूल्यांकन नियमानुसार एवं वास्तविक स्थिति के अनुरूप नहीं किया गया। किसानों ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को सौंपे गए आपत्ति पत्र में उल्लेख किया है कि भूमि की उर्वरता, सिंचाई सुविधाएं, वृक्षों की संख्या तथा स्थायी संरचनाओं को ध्यान में रखते हुए मुआवजे का विधिवत निर्धारण नहीं किया गया है। इससे किसानों को गंभीर आर्थिक क्षति होने की आशंका है।

मुआवजा पुन: निर्धारित करने की मांग- किसानों ने अधिग्रहित भूमि का मुआवजा पुनः निर्धारित करने की मांग की है तथा सभी प्रभावित किसानों को नियमों के अनुसार उचित एवं न्यायसंगत मुआवजा प्रदान किए जाने की अपील की है। किसानों ने स्पष्ट किया है कि जब तक मुआवजे का विधिवत एवं पारदर्शी निर्धारण नहीं किया जाता, तब तक वे अपनी भूमि सौंपने के लिए तैयार नहीं हैं।आवेदन में यह भी मांग की गई है कि भूमि अधिग्रहण के बदले किसानों को चार गुना मुआवजा प्रदान किया जाए, जिससे उनकी आजीविका एवं भविष्य सुरक्षित रह सके। किसानों ने चेतावनी दी है कि मांगें पूरी नहीं होने की स्थिति में वे आंदोलन करने को विवश होंगे।

धार जिले की अंडर-18 क्रिकेट टीम घोषित

धार। इंदौर डिविजनल क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा आयोजित अंतर जिला क्रिकेट स्पर्धा जो खरगोन जिला क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा 30 दिसम्बर से आयोजित की जाएगी इस हेतु धार जिला क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा डी.आर.पी.लाईन मैदान पर चयन ट्रायल आयोजित किया गया। जिसमें अंडर-18 की क्रिकेट टीम का चयन मुख्य चयनकर्ता प्रमोद फाटक, आलोक दुबे,प्रमोद शर्मा ने किया। चयन स्पर्धा में जिले की समस्त तहसीलों के खिलाड़ियों ने भाग लिया चयनित टीम इस प्रकार है । नीलेश पटेल (कसान) मनावर अरमान (केसूर) रोहित काजले (पीथमपुर) दर्शन गांधी (धार) जिगर चौधरी (राजगढ़)आदर्श जाट (धार)कुशल प्रजापत (धार) आदित्य पांडे (पीथमपुर)युवराज (पीथमपुर)मोहम्मद इशा मंसूरी (मनावर) विराट सोमानी (धार) अयान अली (बदनावर) देवांश राठौर (सरदारपुर) हेमंत पाटीदार (मुल्थान) मयूर (धार) अमन दवे (सरदारपुर) चयनित टीम को एसोसिएशन के चेयरमैन करन सिंह पवार, अध्यक्ष प्रदीप जोशी, सचिव राजेन्द्र सिंह चौहान ,उपाध्यक्ष धीरेंद्र दीघे , विनोद मित्तल, डॉ अजेश माइकल ,अमित जैन,युनुस खान धरमपुरी आदि ने बधाई प्रेषित की । यह जानकारी एसोसिएशन के प्रवक्ता कुशल शर्मा ने दी।

अंतर्राष्ट्रीय मानक पूर्ण कर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायसेन बना आईएसओ प्रमाणित प्राधिकरण

रायसेन (निप्र)। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायसेन अब आईएसओ प्रमाणित प्राधिकरण बन गया है। इसका प्रमाण पत्र आज रायसेन में जिला न्यायालय परिसर स्थित एडीआर भवन के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में एनडीआर आईएसओ संस्था के अधिकारीगण श्री जितेन्द्र खंडेलवाल एवं श्री योगेंद्र द्विवेदी द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं प्रधान जिला तथा सत्र न्यायाधीष श्री अनिल कुमार सोहाने को प्रदान किया गया। कार्यक्रम में कलेक्टर श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा, पुलिस अधीक्षक श्री आशुतोष गुप्ता, श्री अरविंद जैन प्रधान न्यायाधीष कुटुम्ब न्यायालय, श्रीमती शशि सिंह विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटी सहित सभी न्यायाधीशगण, श्री अनीस उद्दीन अब्बासी जिला विधिक सहायता अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारीगण, श्री विनयकांत चतुर्वेदी अध्यक्ष जिला अभिभाषक संघ, अधिवक्तागण, विधि छात्र एवं पैरालीगल वालेंटियर सम्मिलित रहे। कार्यक्रम में प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायसेन श्री अनिल कुमार सोहाने द्वारा कार्यालय की पूरी टीम को बधाई देते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय मानक पूर्ण करने पर आईएसओ सर्टिफिकेट प्राप्त होना रायसेन के लिए गौरव की बात है। इस उपलब्धि में विधिक सेवा संस्थान के अधिकारियों, कर्मचारियों, पैनल अधिवक्ताओं, लीगल एड डिफेंस काउंसिल्स व पैरालीगल वालेंटियर्स का पूर्ण योगदान रहा है।

सभी ने समाज के जरूरतमंद एवं अंतिम छोर के व्यक्ति को शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाने में अमूल्य योगदान दिया है। कलेक्टर श्री अरुण कुमार विश्वकर्मा ने कार्यक्रम में उपस्थित प्रशासनिक अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायसेन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और उत्कृष्ट कार्य करते हुए हमें भी आईएसओ प्रमाणीकरण हेतु प्रयास करना चाहिए। पुलिस अधीक्षक श्री आशुतोष गुप्ता द्वारा व्यक्त किया गया कि मुझे इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने पर अत्यंत खुशी हो रही है। आईएसओ अवार्ड लक्ष्य नहीं एक जरिया है। आईएसओ अवार्ड पाना महत्वपूर्ण नहीं है, आईएसओ अवार्ड क्यों पाना है, यह महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम में प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय श्री अरविंद जैन द्वारा कहा गया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायसेन वर्ष 2025 का पहला प्राधिकरण है जिसे आईएसओ अवार्ड प्राप्त हुआ है।

यह पूरे रायसेन जिले के लिए गर्व की बात है। श्रीमती हर्षिणी यादव सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायसेन द्वारा आईएसओ प्रमाणीकरण के संबंध मे जानकारी देते हुए बताया गया कि यह प्रमाणन यह सुनिश्चित करता है कि विधिक सेवा से जुड़ी प्रत्येक प्रक्रिया पारदर्शी एवं उत्तरदायी हो, जिससे आम नागरिकों विशेषकर गरीब, असहाय, महिलाएं, वृद्ध, दिव्यांगजन तथा पीड़ित वर्ग बिना किसी बाधा के निशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सके। कार्यक्रम का संचालन श्रीमती हर्षिणी यादव सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायसेन एवं आभार प्रदर्शन श्री अनीस उद्दीन अब्बासी जिला विधिक सहायता अधिकारी द्वारा किया गया।

संक्षिप्त समाचार

खाद्य सुरक्षा विभाग ने चिचोली में खाद्य प्रतिष्ठानों का किया निरीक्षण

बैतूल (निप्र)। कलेक्टर श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा चलित खाद्य प्रयोगशाला के माध्यम से जिलेभर में खाद्य पदार्थों का विक्रय करने वाले प्रतिष्ठानों की सघन जांच एवं नमूने लिए जाने की कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा प्रशासन श्री शैलेंद्र बड़ोनिया के मार्गदर्शन में 17 दिसंबर को चिचोली तहसील में खाद्य दुकानों का निरीक्षण किया गया। चलित खाद्य प्रयोग शाला में जांच दल खाद्य सुरक्षा अधिकारी मीना कुमरे , केमिस्ट हेमंत कीर, सहायक ब्रजेश पटेल द्वारा विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों अमूल ट्रेडर्स, जायसवाल किराना, ओम साईंकृपा रेस्टोरेंट, गुरुसाहिब किराना, महालक्ष्मी ट्रेड्स की जांच कर कुल 25 नमूने लिए गए। नमूनों की जांच केमिस्ट द्वारा की गई तथा जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। इसके अलावा शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चिचोली में जागरूक कार्यक्रम के तहत मिलावट की जांच के प्राथमिक तरीके बताए गए।

जल संचय अभियान के अंतर्गत आठनेर में बोरी बंधान कार्य संपन्न

बैतूल (निप्र)। जल संचय अभियान के अंतर्गत आठनेर विकासखण्ड में कावला सेक्टर की ग्राम पंचायत गारगुड के डंगरापाटा में खेत की नदी पर 80 बोरियों का बोरी बंधान किया गया। यह कार्य प्रस्फुटन समिति, नवांकुर संस्था, मेंटर एवं सीएमसीएलडीपी कार्यक्रम के छात्रों के संयुक्त सहयोग से सम्पन्न हुआ। बोरी बंधान कार्य में विकासखण्ड समन्वयक श्रीमती मधु चौहान, प्रस्फुटन समिति, नवांकुर संस्था प्रतिनिधि सहित समिति सदस्य एवं सेक्टर के सीएमसीएलडीपी छात्र-छात्राओं ने सक्रिय सहभागिता की। बोरी बंधान कार्य के पश्चात विकासखण्ड समन्वयक द्वारा उपस्थित छात्रों और समिति सदस्यों के साथ चौपाल आयोजित कर वर्षा जल संरक्षण एवं ग्राम स्तर पर अधिक से अधिक बोरी बंधान निर्माण विषय पर चर्चा की गई। साथ ही छात्रों द्वारा अपने-अपने प्रयोगशाला ग्रामों में जल संचय अभियान के अंतर्गत की जाने वाली गतिविधियों की जानकारी साझा की गई।

मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना से परिवार जनों को मिल रही सहायता

विदिशा (निप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी के द्वारा मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना में 7227 हितग्राहियों को 160 करोड रुपए की सहायता राशि का अंतरण किया गया है, जिससे विदिशा जिले के हितग्राही भी लाभांवित हुए हैं। विदिशा जिले की हितग्राही श्रीमती मंजू श्रीवास्तव ने योजना अंतर्गत दो लाख रुपये की राशि अपने बैंक खाते में प्राप्त होने पर जनकल्याण संबल योजना की भूरि भूरि प्रशंसा की है। उन्होंने कहा है कि यह योजना दुख-मुसीबत के समय नागरिकों के साथ खड़ी रहकर आर्थिक संबल प्रदान कर रही है। जिस समय परिवारजन दुखी होते हैं उस समय यह योजना सहारा बन रही है। योजना से लाभान्वित हितग्राही श्रीमती मंजू श्रीवास्तव ने बताया कि उनके पति श्री शैलेश श्रीवास्तव की मृत्यु हो गई थी इसके उपरांत उन्होंने मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना में आवेदन किया और योजना अंतर्गत दो लाख रुपये की राशि प्राप्त हुई है जो उनके परिवार का सहारा बनेगी।

लहसुन एवं प्याज फसलों का निरीक्षण, कीट नियंत्रण व सूक्ष्म सिंचाई पर दिया मार्गदर्शन

सीहोर (निप्र)। उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, जिला सीहोर के सहायक संचालक उद्यान द्वारा विकासखण्ड सीहोर के ग्राम झरखेड़ा में कृषक श्री रमेशचंद्र पाटीदार एवं श्री शिवप्रसाद पाटीदार के प्रक्षेत्र का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान लहसुन एवं प्याज फसलों की स्थिति का अवलोकन कर रसचूसक कीट के नियंत्रण हेतु ईमिडाक्लोप्रिड एवं थायोमेथोक्जाम की अनुशंसित मात्रा में छिड़काव करने की सलाह दी गई। साथ ही फसलों में लगने वाले अन्य कीट एवं रोगों की पहचान, रोकथाम एवं समुचित प्रबंधन के संबंध में कृषकों को विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत कृषकों के खेतों में स्थापित मिनी स्प्रिंकलर प्रणाली का भी निरीक्षण किया गया तथा जल संरक्षण एवं सिंचाई दक्षता बढ़ाने के लिए ड्रिप एवं मिनी स्प्रिंकलर जैसी सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों को अधिक से अधिक अपनाने हेतु कृषकों को प्रेरित किया गया।

बाल विवाह मुक्त भारत के लिए 100 दिवसीय गहन जागरूकता अभियान के अंतर्गत जागरूकता शिविर का आयोजन

बैतूल (निप्र)। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बैतूल श्री दिनेश चन्द्र थपलियाल के निर्देशन में बैतूल जिले को बाल विवाह मुक्त बनाने के लिये 09 दिसम्बर 2025 से 18 मार्च 2026 तक प्रारंभ 100 दिवसीय गहन जागरूकता अभियान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायालय बैतूल द्वारा चलाया जा रहा है।

यह अभियान राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा संचालित योजना नालसा 'आशा' के क्लाज 6 अंतर्गत लागू किया गया है। एनआरएलएम के अंतर्गत लोक अधिकार केन्द्र एवं एनजीओ प्रदान के कार्यकर्ताओ का प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन 17 दिसंबर को एडीआर भवन जिला न्यायालय परिसर बैतूल में किया गया। इस अवसर पर सचिव श्रीमती शर्मिला बिलवार, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री सोमनाथ राय, पैरालीगल वॉलेंटियर्स उपस्थित रहे। प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय श्री शिवबालक साहू ने बताया कि सामाजिक जागरूकता ही इसे रोकने का एकमात्र उपाय है।

हम प्रत्येक कार्यक्रम व अयोजनो के साथ-साथ परिवार में व दोस्तों, पड़ोसियों को इसके दुष्परिणाम बताकर इसे रोकने का प्रयास कर सकते है। शैक्षणिक संस्थाओं में इसकी जानकारी दिया जाना आवश्यक है और परिवार में बच्चो के साथ दोस्ताना व्यवहार कर माता-पिता को उनकी भावनाओं को समझना और परिवार का सकारात्मक वातावरण सबसे अहम है। सचिव श्रीमती शर्मिला बिलवार ने बाल विवाह मुक्त बैतूल बनाने के लिए प्रारम्भ किये गये 100 दिवसीय गहन जागरूकता अभियान में अन्य लोगों को भी शामिल करने अपेक्षा की।

जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री सोमनाथ राय द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा संचालित योजना नालसा 'आशा' एवं बाल विवाह मुक्त भारत के लिये प्रारम्भ किए गए 100 दिवसीय गहन जागरूकता अभियान के बारे में जानकारी दी। इसके अतिरिक्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की समाज व जिले में भूमिका तथा आयोजित किये जाने वाले अभियान एवं कार्यक्रमो के बारे में जानकारी दी। सभी कार्यकर्ताओ ने एडीआर भवन में पॉक्सो कानून, साईबर अपराध, संविधान, यातायात नियम, दहेज कानून, भ्रूण हत्या आदि विषयों को एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली तथा मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा संचालित योजनाओं की प्रर्दशिनी का अवलोकन किया गया।

राजस्व एवं वन विभाग के बीच बेहतर समन्वय से कार्य में गति लाई जाएः कलेक्टर

वन ग्रामों के संपरिवर्तन और वन व्यवस्थापन के कार्य में गति देने के दिये निर्देश राजस्व एवं वन अधिकारियों की संयुक्त बैठक

सीहोर (निप्र)। कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में राजस्व एवं वन विभाग के अधिकारियों की संयुक्त बैठक आयोजित कर वन ग्रामों के राजस्व ग्रामों में संपरिवर्तन तथा वन खण्डों के व्यवस्थापन की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि वन ग्रामों से संबंधित समस्त आवश्यक डेटा वन विभाग द्वारा शीघ्र ही राजस्व विभाग को उपलब्ध कराया जाए, ताकि संपरिवर्तन की प्रक्रिया में किसी प्रकार की देरी न हो। कलेक्टर ने वन अधिकारियों को एक सप्ताह में अभिलेख राजस्व अधिकारियों को देने के निर्देश दिये।

कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने लंबित सामुदायिक दावों का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही ग्रामों की सीमा निर्धारण की प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण करने हेतु राजस्व एवं वन विभाग का संयुक्त दल गठित कर समन्वय से कार्य करने पर बल दिया गया।

बैठक में सभी चिन्हित वन ग्रामों के राजस्व ग्रामों में संपरिवर्तन कार्य में तेजी लाने के लिए संयुक्त कार्ययोजना तैयार कर प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने कहा कि राजस्व एवं वन विभाग के बीच बेहतर समन्वय से कार्य में गति लाई जा सकती है। बैठक में डीएफओ श्रीमती अर्चना पटेल, अपर कलेक्टर श्री वृंदावन सिंह ने भी राजस्व एवं वन अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये। बैठक में संयुक्त कलेक्टर श्री रविन्द्र परमार, सभी एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एसएलआर तथा वन विभाग के एसडीओ, रेंजर, डिप्टी रेंजर तथा वनपाल सहित सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

श्री माखनलाल चतुर्वेदी शासकीय महाविद्यालय माखननगर में रोजगार मेला सम्पन्न

449 विद्यार्थियों में से 164 का किया गया प्राथमिक चयन

नर्मदापुरम (निप्र)। कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना के निर्देशन में माखन नगर स्थित श्री माखनलाल चतुर्वेदी शासकीय महाविद्यालय में आयोजित रोजगार एवं स्वरोजगार मेले का सफल समापन हुआ। महाविद्यालय परिसर में आयोजित इस मेले में मुख्य अतिथि एवं कार्यक्रम अध्यक्ष के रूप में जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष श्री सुरेश अग्रवाल उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथि के तौर पर श्री मनीष चतुर्वेदी एवं समस्त जनप्रतिनिधि द्वारा हितग्राहियों को ऋण प्रमाणपत्र वितरित किए। मेले में नर्मदापुरम के एसडीएम विजेंद्र सिंह रावत ने छात्र-छात्राओं को रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसरों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। तहसीलदार डॉ. सुरेखा यादव ने भी अपने अनुभव साझा करते हुए रोजगार सृजन की दिशा में मार्गदर्शन किया। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. नीता चौबे ने अपने उद्बोधन में विद्यार्थियों को अधिक से अधिक रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर नगर पालिका अधिकारी श्री सीएसराजपूत, डॉ. प्रेमा अरविंद (मेडिकल ऑफिसर), श्री कमलेश ठाकुर, श्री देवी सिंह राजपूत, श्री राजेंद्र सिंह राजपूत, श्री नरेश मलिक, श्री उमेश तिवारी (पत्रकार) तथा जिला व्यापार उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक प्रकाश कुमार (इंदौर) सहित कई गणमान्य उपस्थित रहे। तथा जिला रोजगार कार्यालय नर्मदापुरम श्री धर्मेश तिवारी प्लेसमेंट ऑफिसर के कुशल नेतृत्व में संपूर्ण रोजगार मेले सफल आयोजन हुआ एवं अजय मेहरा डॉ अमिताभ शुक्ला डॉक्टर क्षमा मेहरा मंच संचालन डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह चौहान एवं डॉक्टर मनीष शर्मा के द्वारा किया गया। डॉ राजकुमार पटवा, डॉक्टर आकांक्षा यादव पंजीयन काउंटर पर श्री पंकज बैरवा, श्रीमती मंजू मेहरा, श्रीमती सुषमा यादव, डॉ संगीता मिश्रा कुमारी शिवानी मालवीय, डॉक्टर कविता दुबे, श्रीमती संध्या गोलियां, डॉ सुमन अवस्थी, एवं अशोक मेहर सहित समस्त महाविद्यालय स्टॉप उपस्थित रहे। रोजगार मेले में कुल 449 छात्र-छात्राओं ने भाग लिया। 12 निजी कंपनियों और 5 शासकीय विभागों ने स्टॉल लगाकर रोजगार के अवसर प्रस्तुत किए। प्राथमिक चयन के आधार पर 152 उम्मीदवारों का चयन किया गया, जबकि स्वरोजगार योजना के तहत 12 लाभार्थियों को सहायता प्रदान की गई। इस प्रकार कुल 164 छात्र-छात्राओं को प्रत्यक्ष लाभ मिला। स्वास्थ्य विभाग ने मेले में 65 विद्यार्थियों की स्वास्थ्य जांच की।

आर्थिक सहायता जारी

विदिशा (निप्र)। कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता ने हिट एण्ड रन के एक प्रकरण में 15 हजार रूपए की आर्थिक सहायता मृतक के परिजन को जारी कर दी है। डिप्टी कलेक्टर एवं नोडल अधिकारी सुश्री निकिता तिवारी ने जारी आर्थिक सहायता आदेश का हवाला देते हुए बताया कि ज्ञात वाहन दुर्घटना में शमशाबाद तहसील के ग्राम हीरापुर के फूल खां पुत्र अक्कल खां की मृत्यु हो जाने पर मृतक की पत्नी श्रीमती सियाबाई को 15 हजार रूपए की आर्थिक सहायता जारी की गई है।

कलेक्टर श्री विश्वकर्मा की अध्यक्षता में बंधक श्रम प्रथा उन्मूलन एवं बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम संबंधी बैठक सम्पन्न

रायसेन (निप्र)। कलेक्टर श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा की अध्यक्षता में बंधक श्रम प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम 1976 के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय बंधक श्रम समिति और बाल एवं कुमार (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 के अंतर्गत गठित टास्क फोर्स समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने जिले में बंधक श्रम प्रथा उन्मूलन अधिनियम एवं बाल एवं कुमार (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियमों का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए। साथ ही इन अधिनियमों के प्रावधानों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के भी निर्देश दिए। कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने बंधक श्रम प्रथा एवं बाल श्रमिकों की रोकथाम हेतु नियमित रूप से निरीक्षण करने एवं सभी व्यावसायिक संस्थानो में बाल श्रम निषेध सम्बन्धी एडवाइजरी चस्पा होना अनिवार्यतः सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में श्रम पदाधिकारी श्री जीएस महदेले द्वारा समिति के सदस्यों को बाल श्रम प्रथा एवं बाल श्रमिक से जुड़े विभिन्न प्रावधानों की जानकारी दी गई।

साथ ही बाल श्रम प्रथा के सम्बन्ध में दायित्वों से अवगत कराते हुए बंधुआ मजदूरों को बचाने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में विस्तार से बताया गया। बैठक में बाल कल्याण समिति अध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा बाल श्रम की रोकथाम हेतु महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए। बैठक में अपर कलेक्टर श्री अपर कलेक्टर श्री मनोज उपाध्याय, महिला एवं विकास विभाग के जिला कार्यकम अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

राजस्व, कृषि एवं उद्यानिकी विभाग का संयुक्त निरीक्षण भ्रमण

विदिशा (निप्र)। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री अंशुल गुप्ता द्वारा विदिशा जिले में नवाचार को लेकर जारी मुहिम को दृष्टिगत रखते हुए नटेरन एसडीएम श्री अजय प्रताप सिंह पटेल की अध्यक्षता में प्रगतिशील कृषकों द्वारा लगाए गए खेती के नवाचारों का निरीक्षण किया गया।

ड्रैगन फ्रूट की खेती बनी आकर्षण का केंद्र

नटेरन एसडीएम श्री अजय प्रताप सिंह पटेल द्वारा अपने कार्यक्षेत्र में ड्रैगन फ्रूट की खेती की पहल अपना रहे प्रगतिशील कृषक श्री विपुल श्रीवास्तव के खेत का भ्रमण किया, जिसमें उनके द्वारा अपनाए जा रहे उन्नत कृषि तकनीकों द्वारा ड्रैगन फ्रूट के साथ-साथ नींबू एवं आम की उन्नत किस्मों के बारे में विस्तार से जानकारी ली गई।

पारंपरिक फसलों के साथ चिया सीड्स एवं कलौंजी का सामंजस्य

एसडीएम श्री पटेल द्वारा ग्राम काशीपुर के कृषक श्री बृजेश तिवारी द्वारा अपने खेत में गेहूं के साथ चिया सीड्स की खेती 3 हेक्टेयर की खेती का भी भ्रमण किया गया। इसके साथ ही ग्राम के कृषक श्री कल्याण सिंह जी के 6 हेक्टेयर के कलौंजी की खेती के बारे में भी जानकारी ली गई। ग्राम के कृषकों द्वारा बताया गया कि इस वर्ष लगभग 80 हेक्टेयर से अधिक में चिया सीड्स की खेती की गई है।

कृषकों एवं अधिकारियों के मध्य संवाद

एसडीएम श्री पटेल द्वारा चिया सीड्स को पारंपरिक खेती में अपनाने से चिया सीड्स में मवेशियों द्वारा फसल क्षति, बेमौसम फसल नुकसान, उर्वरकों का कम मात्रा में प्रयोग इत्यादि को देखते हुए उक्त फसल की बुवाई पर जोर दिया जाए। नटेरन तहसीलदार श्री आनंद जैन द्वारा चिया सीड्स , कलौंजी, एवं अन्य उद्यानिकी फसलों में होने वाले प्राकृतिक प्रकोपों से होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति की जानकारी भी कृषकों को दी गई। सहायक संचालक उद्यानिकी श्री सोलंकी द्वारा

ड्रैगन फ्रूट की किस्मों एवं इसके लाभकारी गुणों जैसे - फोलिक एसिड, विटामिन सी, हृदय रोगों, पाचन तंत्र मजबूत करने इत्यादि के बारे में जानकारी प्रदाय की गई। उद्यानिकी से श्री रामचंद्र वर्मा द्वारा पीएमकेएसवाय योजनांतर्गत ड्रिप सिंचाई के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। कृषि विस्तार अधिकारी श्री अभिषेक जैन द्वारा चिया सीड्स के बुवाई से लेकर प्रोसेसिंग एवं बाजार मूल्य के विषय में विस्तार से बताया गया जिसमें मुख्यतः उर्वरक की मात्रा का पारंपरिक फसलों से 25: कम उपयोग करने एवं बाजार मूल्य लगभग 25000 प्रति क्विंटल होने के विषय में जानकारी प्रदाय की गई।

खेती में हो रहा उन्नत कृषि यंत्रों का उपयोग

एसडीएम श्री पटेल द्वारा कृषक श्री कल्याणसिंह के फॉर्म हाउस पर रखे अपने खेत में उपयोग होने वाले कृषि यंत्र जिसमें मुख्यत : उर्वरक के समुचित मात्रा में वितरण हेतु फर्टिलाइजर ब्रॉडकास्टर, भूसा बनाने हेतु नरवाई प्रबंधन के लिए स्ट्रा रीपर, रोटावेटर एवं अन्य कृषि यंत्र भी देखे गए। राजस्व, कृषि एवं उससे संबद्ध विभागों के संयुक्त निरीक्षण भ्रमण के दौरान नटेरन तहसीलदार श्री आनंद जैन, शमशाबाद तहसीलदार, नायब तहसीलदार श्री दर्शनलाल नेगी, सहायक संचालक उद्यानिकी श्री श्यामलाल सोलंकी, प्रभारी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी श्री जगदीश गुर्जर, उद्यानिकी से श्री रामचंद्र वर्मा, प्रभारी उद्यान विकास अधिकारी श्री कुंदन सिंह, क्षेत्रीय कृषि विस्तार अधिकारी श्री राघवेंद्र अहिरवार, कृषि विभाग से श्री सत्यम नेमा, श्री रजत जैन, श्री अभिषेक जैन एवं अन्य विभागीय अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री का बैतूल में मेडिकल कॉलेज की सौगात के लिए विधायकों ने माना आभार

मुख्यमंत्री से अध्यक्ष खण्डेलवाल के नेतृत्व में बैतूल के विधायकों ने की भेंट

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से बैतूल विधायक तथा प्रदेश अध्यक्ष श्री हेमंत खंडेलवाल के नेतृत्व में बैतूल जिले के विधायकों ने भेंट कर बैतूल को मेडिकल कॉलेज तथा अन्य सौगातें देने के लिए मुख्यमंत्री का आभार माना। मुख्यमंत्री निवास पर हुई भेंट में विधायक सर्वश्री महेंद्र सिंह चौहान, डॉ. योगेश पंडाग्रे, चंद्रशेखर देशमुख तथा श्रीमती गंगाबाई उईके मौजूद रहीं।

विधायकों ने कहा कि जनजातीय और ग्रामीण बहुल बैतूल जिले में मेडिकल कॉलेज खुलने से ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्र के मरीजों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा जिले में ही मिल सकेगी। इससे स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार हो सकेगा। पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना से क्षेत्र के विद्यार्थियों को मेडिकल की पढ़ाई में भी सुविधा होगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जे. पी. नड्डा बैतूल जिले के कोसमी क्षेत्र में पीपीपी मोड पर आरंभ हो रहे मेडिकल कॉलेज का 23 दिसम्बर को भूमि-पूजन करेंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव का विधायकों ने सारणी के सतपुड़ा ताप विद्युत गृह में लगभग 12 हजार करोड़ रुपए की लागत की 660 मेगावाट यूनिट इकाई की स्थापना की वर्षों पुरानी मांग स्वीकृत करने, भीमपुर में 100 बिस्तरीय अस्पताल और चिचोली में 50 बिस्तरीय अस्पताल की स्वीकृति देने के लिए भी आभार माना। मुख्यमंत्री डॉ. यादव से घोड़ाडोंगरी विधायक श्रीमती गंगा बाई उईके ने चोपना क्षेत्र के परिवारों के पट्टों के प्रकरणों के निराकरण के संबंध में भी अनुरोध किया।

5 नंबर री-डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को टीएनसीपी से मंजूरी

एमपी हाउसिंग बोर्ड ने मुहर लगाई, ईएमसी-2.0 का 121 करोड़ का टेंडर फाइनल

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश के पहले री-डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रविशंकर शुक्ल मार्केट के विकास का रास्ता साफ हो गया है। भोपाल के 5 नंबर स्थित आरएसएस मार्केट प्रोजेक्ट को हाउसिंग बोर्ड की संचालक मंडल की बैठक में प्रशासकीय स्वीकृति मिल गई। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (टीएनसीपी) से भी इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई है। अब नए साल में बोर्ड इसके लिए टेंडर जारी करेगा।

वहीं, 210 एकड़ में 371 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर 2.0 प्रोजेक्ट के पहले चरण का टेंडर फाइनल हो गया। यह 121 करोड़ रुपए का टेंडर था। बोर्ड बैठक की अध्यक्षता मंडल के चेयरमैन व नगरीय आवास एवं विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने की। बैठक में विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय दुबे, वित्त विभाग के उप सचिव आनंद पटले, टीएनसीपी के संयुक्त संचालक केएस गवली, हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर राहुल हरिदास फटिंग, बोर्ड की मुख्य प्रशासकीय अधिकारी तृप्ति श्रीवास्तव मौजूद थे।

हर सुविधा एक ही छत के नीचे- राजधानी की बैरसिया तहसील के ग्राम बांदीखेड़ी में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (ईएमसी 2.0) के डेवलपमेंट का टेंडर फाइनल हो गया। पहले राउंड का यह टेंडर 121 करोड़ रुपए का है। 371 करोड़ रुपए की लागत से 210.21 एकड़ में यह प्रोजेक्ट विकसित किया जा रहा है। इस पूरे प्रोजेक्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन व विनिर्माण इंडस्ट्री से जुड़ी हर सुविधा एक ही छत के नीचे होगी। पूरे प्रोजेक्ट को कवर्ड कैंपस में बिजनेस पार्क के तौर पर विकसित किया जाएगा। इसमें एक एकड़ से लेकर 5 एकड़ तक के कमर्शियल प्लाट आईटी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को अलर्ट किए जाएंगे। इस कैंपस में एसटीपी, इटीपी से लेकर कैफेटेरिया जैसी सुविधाएं होंगी।

मंत्री विजयवर्गीय बोले- स्मार्ट सिटी का काम दिखता नहीं,जमीन के नीचे 200 करोड़ खर्च हुए, फिर भी लोगों ने गालियां दीं, इंदौर-भोपाल का मास्टर प्लान तैयार

मप्र की मोहन सरकार के दो साल पूरे होने पर नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अपने विभाग की दो सालों की उपलब्धियां गिनाईं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री विजयवर्गीय से पत्रकारों ने पूछाः 2014 में बीजेपी सरकार ने स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया था। पूर्व मुख्यमंत्री जी ने हर जगह स्मार्ट सिटी की घोषणा की? सिंगरौली, सतना, भोपाल ग्वालियर पूरे प्रदेश में स्मार्ट सिटी अनाउंस की। सौ करोड़ रूपए आया। उसमें अब तक कहां-कहां स्मार्ट सिटी बन चुकी हैं?

इस सवाल के जवाब में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा- नगर निगम के कुछ काम विजिबल होते हैं और कुछ विजिबल नहीं होते हैं। जैसे स्मार्ट सिटी में बहुत बड़ी ड्रेनेज लाइन डल गई। भोपाल, सतना में जब ड्रेनेज लाइन डल रही थी तो लोगों को बहुत परेशानी हो रही थी। क्योंकि, बड़ी मेन ड्रेनेज लाइन डल रही थी। पूरी सड़क खुदी हुई थी मार्केट में से निकल रही थी। लोगों ने बहुत गालियां दीं, अखबारों ने खूब छापा। अब वो बन गई उसके ऊपर सड़क बन गई। वो कितने करोड़ की है मुझे पता नहीं। लेकिन, वो शहर की आवश्यकता थी। विजयवर्गीय ने कहा- ऐसे ही वाटर सप्लाई के लिए डिस्ट्रीब्यूशन लाइन डालते हैं। शहर में खुदाई होती है उसे बाद में रिस्टोर करते हैं। पैसा जमीन के अंदर खर्च हो जाता है वो दिखाई देता नहीं, लोग हमसे कहते हैं आपने स्मार्ट सिटी का पैसा कहां लगा दिया, सिटी तो स्मार्ट हुई नहीं? सिटी स्मार्ट हुई है। विजयवर्गीय ने कहा-लोगों के घर तक पानी पहुंच रहा है। उनके घर में ड्रेनेज भरा रहता था अब घर साफ रहता है। ये ऐसी चीजें हैं जो विजिबल है। कुछ विजिबल हैं कुछ नॉन विजिबल हैं। इसलिए लोग कहते हैं कि नगर निगम का तीन सौ करोड़ रूपया खर्च हो गया, कहां चला गया? भई जमीन के अंदर दो सौ करोड़ रुपया हैं आपको दिख नहीं रहे हैं। इसलिए प्रश्न उठते हैं। वो इसलिए नहीं दिख रहे क्योंकि जमीन के अंदर जो काम होता है वो नहीं दिखता। हमने जो ड्रेनेज लाइन डाली है वो 5-10 और 20 साल की जनसंख्या कितनी होगी उसके हिसाब से डालते हैं उसमें बड़ा खर्चा होता है।

शहरी विकास मंत्रियों की क्षेत्रीय बैठक भोपाल में आज

बैठक में मुख्यमंत्री और केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल भी रहेंगे मौजूद

भोपाल (नप्र)। केन्द्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के तत्वावधान में शहरी विकास मंत्रियों की क्षेत्रीय बैठक (उत्तरी एवं मध्य राज्यों) 20 दिसंबर शनिवार प्रातः 11 बजे कुशाभाऊ ठाकरे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र, भोपाल में आयोजित हो रही है। बैठक का मुख्य उद्देश्य प्रमुख शहरी विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच सहयोग और समन्वय को सुदृढ़ करना है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आयुक्त श्री संकेत भोंडवे ने बताया कि यह बैठक राज्यों को योजना-वार प्रगति प्रस्तुत करने, क्रियान्वयन से जुड़ी समस्याओं को साझा करने, श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों के आदान-प्रदान तथा मंत्रालय से नीतिगत एवं रणनीतिक मार्गदर्शन प्राप्त करने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करेगी।

क्षेत्रीय बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, केन्द्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल और प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय की उपस्थिति रहेगी। इसके साथ ही छत्तीसगढ़, दिल्ली, राजस्थान एवं उत्तरप्रदेश के शहरी विकास मंत्री एवं राज्यमंत्री, भारत सरकार एवं राज्यो के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में सहभागिता करेंगे। कार्यक्रम का एक प्रमुख आकर्षण स्वच्छ सर्वेक्षण वर्ष 2025-26 के लिए कार्य-दिशा पुस्तिका का विमोचन होगा। इस संबंध में नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आयुक्त श्री संकेत भोंडवे ने बताया कि यह कार्य-दिशा पुस्तिका स्वच्छता, स्थायित्व तथा नागरिक-केंद्रित शहरी प्रशासन को और अधिक सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

पाँच सत्रों में महत्वपूर्ण विषयों पर होगी चर्चा

बैठक के दौरान पाँच सत्रों में शहरी विकास से जुड़े प्रमुख विषयों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। इन सत्रों के माध्यम से केंद्र एवं राज्यों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा और योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही व्यवहारिक चुनौतियों का समाधान निकाला जा सकेगा। अमृत योजना के अंतर्गत संचालित एवं प्रस्तावित कार्यों की प्रगति, गुणवत्ता तथा समयबद्ध पूर्णता से संबंधित विषयों पर विचार किया जाएगा। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये आवश्यक सुधारात्मक कदमों पर भी मंथन होगा। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत डंप स्थलों के वैज्ञानिक प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट निपटान तथा स्वच्छता से जुड़ी चुनौतियों पर मंथन होगा। स्वच्छता व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार की जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत निर्माणाधीन एवं स्वीकृत आवासों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी तथा लाभार्थियों को समय पर आवास उपलब्ध कराने में आ रही समस्याओं के समाधान पर विचार किया जाएगा। अंगीकार अभियान की वर्तमान स्थिति, उपलब्धियों एवं चुनौतियों की समीक्षा करते हुए अभियान को अधिक प्रभावी एवं जनसहभागिता आधारित बनाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश तय किए जाएंगे। सत्र में शहरी परिवहन व्यवस्था के अंतर्गत नगर बस सेवाओं, भूमिगत रेल प्रणाली तथा पैदल मार्गों से संबंधित आवागमन व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी।

मैरिज सर्टिफिकेट अब ऑनलाइन मिलेंगे

रजिस्ट्रेशन के लिए घर बैठे ही आवेदन कर सकेंगे, निगम की नई पहल

भोपाल (नप्र)। भोपाल में मैरिज सर्टिफिकेट अब ऑनलाइन ही मिलेंगे। लोग घर बैठे ही रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। निगम ने यह पहल की है। इस संबंध में निगम कमिश्नर संस्कृति जैन गुरुवार को बैठक भी कर चुकी हैं। कमिश्नर जैन ने अफसरों से कहा है कि लोगों को विवाह पंजीयन की ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सभी कार्रवाई जल्दी पूरी करें।

इस तरह होगी पूरी प्रक्रिया- कमिश्नर जैन ने बताया मैरिज सर्टिफिकेट ऑनलाइन ही जारी किए जाएंगे। इसके लिए निगम की वेबसाइट पर जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। फिर वार्ड में पदस्थ निगम कर्मचारी अपलोडेड दस्तावेजों के आधार पर स्थल पर जाकर पंचनामा आदि बनाएंगे और दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे। इसके बाद डिजिटल मैरिज सर्टिफिकेट संबंधित व्यक्ति डाउनलोड कर सकेंगे। इस प्रक्रिया से नागरिकों को मैरिज सर्टिफिकेट के लिए निगम कार्यालय नहीं आना पड़ेगा। घर बैठे ही मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाएगा।

यह दस्तावेज लगेंगे- दूल्हा-दुल्हन, माता-पिता और गवाहों के आधार कार्ड। शादी का कार्ड और जहां शादी हुई, वहां का प्रमाण पत्र।

मैरिज शाखा के अधिकारी केवल दूल्हा-दुल्हन को ऑफिस बुलाएंगे।

आवेदन से सर्टिफिकेट तक की प्रक्रिया

- निगम की वेबसाइट www.bmconline.gov.in पर जाएं।
- होमपेज पर सिटीजन सर्विसेज के विकल्प पर क्लिक करें।
- यहां मैरिज रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर जानकारी और दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करें।
- दस्तावेज अपलोड होते ही 1100 रुपए ऑनलाइन पेमेंट करना होगा।

जोनल अधिकारी और एएचओ आवेदक के घर जाकर भौतिक सत्यापन करेंगे और प्रमाणपत्र देंगे।

50 दिन तक कोई भी शिकायत पेंडिंग न हो- बैठक में कमिश्नर जैन ने अन्य कार्यों की समीक्षा भी की। कहा कि 50 दिन तक कोई भी शिकायत लंबित नहीं रहनी चाहिए। उक्त अवधि में ही शिकायतों को निराकृत कर विलोपित कराएं अन्यथा संबंधितों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजस्व वसूली की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि संपत्ति कर एवं बकाया करों विशेषकर बड़े बकायादारों से प्रभावी ढंग से करों की राशि वसूल की जाए। उन्होंने लीज रेंट की राशि भी सख्ती के साथ जमा कराने के निर्देश दिए।

दिग्विजय ने गडकरी से कहा-अधूरे हाईवे पर टोल वसूल रहे

राज्यसभा में बोले- आपने अफसरों को फटकारा था फिर भी वसूली जारी, ये अन्याय है

बैतूल (नप्र)। मध्य प्रदेश में बैतूल-भोपाल नेशनल हाईवे (एनएच-46) के अधूरे निर्माण कार्य के बावजूद टोल वसूली जारी रहने का मुद्दा संसद तक पहुंच गया है। गुरुवार को राज्यसभा में कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने यह मामला उठाते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से जवाब मांगा और इसे जनता के साथ अन्याय बताया। सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा कि वे नितिन गडकरी को देश के सबसे प्रभावशाली और कुशल मंत्रियों में मानते हैं, लेकिन अधूरी और खराब सड़कों पर टोल वसूली उचित नहीं है। मंत्री स्वयं बैतूल आकर सड़क की हालत देख चुके हैं और अधिकारियों को फटकार भी लगा चुके हैं, फिर भी टोल बंद नहीं होना चिंताजनक है।

केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी 25 अक्टूबर 2015 को सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने बैतूल-भोपाल नेशनल हाईवे का निरीक्षण किया था।

कुंडी टोल प्लाजा के पास वसूली

यह मामला खासतौर पर शाहपुर के पास स्थित कुंडी टोल प्लाजा से जुड़ा है। बैतूल से इटारसी तक सड़क के कई हिस्सों में गड्ढे, अधूरा डामरीकरण और चल रहे निर्माण कार्य के कारण वाहन चालकों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। स्थानीय लोग और वाहन चालक लंबे समय से टोल वसूली का विरोध कर रहे हैं।

नीति बदलाव की उठी मांग

स्थानीय नागरिकों और सामाजिक संगठनों का कहना है कि जब तक सड़क पूरी तरह मानक ड्राइविंग गुणवत्ता के अनुरूप नहीं बन जाती, तब तक टोल वसूली पर रोक लगनी चाहिए। संसद में मुद्दा उठने के बाद उम्मीद है कि केंद्र सरकार अधूरी या खराब सड़कों पर टोल वसूली को लेकर स्पष्ट नीति बनाएगी।

कोर्ट में 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' जैसा था नजारा

पेशी पर आए रेप के आरोपी पर टूट पड़ी युवकों की भीड़, पुलिस ने बचाई जान

सतना (नप्र)। मध्य प्रदेश का सतना जिला अदालत परिसर अखाड़े में तब्दील हो गया। पुलिस दुष्कर्म, हत्या के प्रयास और अड़ीबाजी के एक कुख्यात आरोपी को पेशी पर लेकर पहुंची थी। तभी पहले से घात लगाए बैठे 25 से अधिक लोगों ने आरोपी पर हमला बोल दिया। फिल्मी स्टाइल में हुई इस वारदात में भीड़ ने पहले से मौजूद आरोपी के भाई को जमकर पीटा दिया।

भाई को पीटने के बाद भीड़ ने फिर आरोपी को पुलिस कस्टडी से खींचने का प्रयास किया। करीब 15 मिनट तक चले इस हाई-वोल्टेज ड्रामे के बीच वकीलों और पुलिस ने सूझबूझ दिखाई। पुलिसकर्मी आरोपी को खींचते हुए कोर्ट के अंदर ले गए और भीड़ से किसी तरह उसकी जान बचाई।

25 से ज्यादा थे हमलावर- प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, यह हमला पूरी प्लानिंग के साथ किया गया था। जानकारी मुताबिक आरोपी शुभम पाल को लेकर कोलगवां पुलिस कचहरी पहुंची थी। जैसे ही पुलिस गाड़ी कचहरी के पश्चिमी गेट पर रुकी, वहां पहले से मौजूद एक गुट ने उसे घेर लिया। हमलावर करीब 25 से ज्यादा थे, जो पुलिस को चकमा देने के लिए 10-10 के छोटे समूहों में कोर्ट परिसर में बिखरे हुए थे। इशारा मिलते ही सब एक साथ टूट पड़े।

वकीलों ने किया बीच बचाव- आरोपियों ने सबसे पहले मौके पर मौजूद शुभम के भाई को निशाना बनाया और उसकी पिटाई शुरू कर दी। इसके बाद वे आरोपी शुभम पाल की ओर लपके। हंगामा देख मौके पर मौजूद वकील दौड़े और बीच-बचाव किया। स्थिति बिगड़ते देख पुलिसकर्मी शुभम को भीड़ के चंगुल से निकालकर दौड़ते हुए कोर्ट भवन के अंदर ले गए। इस दौरान करीब 15 से 20 मिनट तक कोर्ट परिसर में अफरा-तफरी का माहौल रहा। अतिरिक्त पुलिस बल के आने की भनक लगते ही ज्यादातर हमलावर भाग निकले, लेकिन पुलिस ने मौके से दो लोगों को हिरासत में ले लिया है।

दो पकड़ाए अन्य की तलाश जारी- सीएसपी देवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि शुभम पाल एक आदतन अपराधी है। उस पर दुष्कर्म, हत्या का प्रयास और हवाई फायर के मामले दर्ज हैं। वह लंबे समय से फरार था और उस पर 10 हजार रुपये का इनाम घोषित था। कोलगवां पुलिस ने उसे 17 दिसंबर की रात नई बस्ती से गिरफ्तार किया था। पकड़ने के बाद उसे न्यायालय में पेश करने के लिए ले गए थे।

इसी दौरान दुष्कर्म पीड़िता के पक्ष का गुट कोर्ट पहुंच गए थे, जिन्होंने मारपीट की कोशिश की है। इसमें पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लिया है। बाकी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।

नेताओं के लिए काम करने वाला नहीं चाहिए... इसको सस्पेंड करो, कलेक्टर ने पटवारी की बत्ती बुझा दी

दतिया (नप्र)। नेताओं का नहीं, हमें जनता का काम करना चाहिए... झूठ बोल रहे पटवारी को दतिया कलेक्टर ने पावर दिखाए हैं। साथ ही वहां मौजूद अधिकारियों को उसे तुरंत सस्पेंड करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा है कि यह नौकरी में नहीं रहेगा। तुरंत इसकी डीई बनाओ। इस दौरान वहां मौजूद बाकी अधिकारी सन्न रह गए। एसडीएम ने पटवारी को सस्पेंड करने का आदेश जारी कर दिया।

दतिया से 80 किमी दूर पहुंचे कलेक्टर- दरअसल, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े 80 किमी दूर बसई पहुंचे। यहां सांदीपनी स्कूल में जनसुनवाई की। इसमें बसई हल्का पटवारी सत्येंद्र शर्मा कलेक्टर के पास पहुंचे। कलेक्टर के पास एक नाली की शिकायत आई थी। पटवारी का कहना

था कि नाली नहीं है। बाकी अन्य अधिकारी और पुलिस के अधिकारी कह रहे थे कि नाली है लेकिन टेढ़ी। पटवारी किसी नेता के दबाव में झूठ बोले जा रहा था। इसी बात को लेकर कलेक्टर का पारा चढ़ गया।

इसे सस्पेंड करो- दतिया कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े का पारा चढ़ गया था। उन्होंने एसडीएम से कहा कि जो नेताओं के लिए काम करते हैं, ऐसे आदमी नहीं चाहिए। इसे सस्पेंड करो और अच्छे आदमी को रखो। उन्होंने तहसीलदार से कहा कि आप आज ही नाली सीधी बनवाओ अन्यथा आपको भी सस्पेंड करा दूंगा।

नाली को लेकर थी शिकायत

दरअसल, बसई में लंबे समय से नाली निर्माण चल रहा है। कुछ लोगों के मकान रोड से सटकर बने हैं, जिसके चलते उन मकानों को बचाने नाली को तिरछा कर दिया। 16 जुलाई 2025 को कलेक्टर बसई में पहुंचे थे, तब भी यही शिकायत आई थी। तब कलेक्टर ने नाली को सीधा बनाने के निर्देश दिए थे। बुधवार को पुनः जनसुनवाई में बसई निवासी श्रेया पुत्री दिनेश लखेरा ने आवेदन देकर बताया कि उसकी पड़ोसी ने घर की सीमा से आगे बढ़कर मेरे घर के सामने अवैध नाली निर्माण कर ऊपर दीवार खड़ी की जा रही है। जनसुनवाई में ज्यादातर लोगों ने पटवारी सत्येंद्र शर्मा पर सही काम न करने के आरोप लगाए। जिसके चलते कलेक्टर ने मौके पर ही पटवारी को सस्पेंड कर विभागीय जांच करने के भी निर्देश दिए।

एसडीएम संतोष तिवारी ने पटवारी के निलंबन का आदेश जारी कर दिया। हालांकि जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर के तेवर को देखकर पटवारी की सिटीपिटी गुम थी। सोशल मीडिया पर अब यह वीडियो वायरल हो रहा है।